वर्ष: 3 अंक: 10

न्यू इंडिया समाचार

16-30 नवंबर, 2022 (नि:शुल्क)

स्वयं सहायता समूह बने राष्ट्र सहायता समूह

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय आजीविका मिशन दे रहा है नारी शक्ति को नई पहचान और नई दिशा, छोटे-छोटे समूहों से महिलाएं तय कर रही हैं स्वावलंबन की नई राह, अपने सामर्थ्य और संकल्प के कारण स्वयं सहायता समूह सही अर्थ में बन रहे हैं राष्ट्र सहायता समूह...

“सोलर और स्पेस सेक्टर में भारत की उपलब्धियां देख दुनिया हैरान है”

सूर्य उपासना की परंपरा इस बात का प्रमाण है कि हमारी संस्कृति, आस्था का प्रकृति से कितना गहरा जुड़ाव है। परंपरा और विज्ञान को जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के प्रयासों और उसके महत्व पर विस्तार से बात की। वहीं आस्था के महापर्व ‘छठ’ को एक भारत-श्रेष्ठ भारत से जोड़ते हुए पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना जीवन खपा देने वाले लोगों का जिक्र करने के साथ ही सूर्य ग्राम मोढेरा के लोगों से संवाद भी किया। पेश है ‘मन की बात’ के अंश:

- **सूर्य ग्राम:** मोढेरा सूर्य ग्राम के अधिकांश घरों में सौर ऊर्जा से बिजली पैदा होना शुरू हो गया है। कई घरों में अब महीने के आखिर में बिजली बिल नहीं आ रहा है, बल्कि बिजली आय का स्रोत बन चुकी है। वह दिन दूर नहीं जब भारत में सूर्य ग्राम का निर्माण एक बड़ा जन आंदोलन बन जाएगा।
- **छठ पूजा का महत्व:** छठ पूजा ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें पूजा के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को विभिन्न समुदायों द्वारा मिलकर तैयार किया जाता है। यह त्योहार हमारे जीवन में स्वच्छता के महत्व पर भी जोर देता है।
- **सूर्य और विज्ञान:** आज जहां पूरी दुनिया सौर ऊर्जा की ओर देख रही है, वहीं हमारे देश में सूर्य भगवान हमेशा से पूजनीय रहे हैं और वे हमारे जीवन का केंद्र हैं। भारत अपने पारंपरिक तरीकों को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ रहा है। आज भारत सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है।
- **सोलर पंप और जीवन:** भारत, सौर ऊर्जा का भरपूर उपयोग करते हुए देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन को बदल रहा है। कांचीपुरम, तमिलनाडु के किसान थिरू के. एजिलॉन ने पीएम कुसुम योजना के तहत अपने खेत में सोलर पंप लगाया, जिससे उन्हें बिजली के खर्च से राहत मिली। राजस्थान के भरतपुर के एक अन्य लाभार्थी कमल मीणा ने अपने खेत में सोलर पंप लगाया, जिससे उनका खर्च कम होने के साथ रोजगार का भी सृजन हुआ।
- **सौर ऊर्जा से बचत:** सूर्य की शक्ति से अब धन की बचत होगी और आय में वृद्धि होगी। श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर के मंजूर अहमद लर्हवाल ने सोलर रूफटॉप प्लांट लगाया जिससे उनके खर्च में कमी आई। ओडिशा की कुन्नी देउरी सौर ऊर्जा से चलने वाली रीलिंग मशीन का उपयोग कर आदिवासी महिलाओं को सिल्क की कताई का प्रशिक्षण देती है जिससे बिजली भी बच रही है।
- **अंतरिक्ष क्षेत्र:** मेरा ध्यान अंतरिक्ष की तरफ जा रहा है। वो इसलिए, क्योंकि हमारा देश, सोलर सेक्टर के साथ ही अंतरिक्ष क्षेत्र में भी कमाल कर रहा है। पूरी दुनिया आज भारत की उपलब्धियां देखकर हैरान है। अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स के लिए दरवाजे खुलने से, देश के युवाओं के लिए भी नए अवसर के द्वार खुल चुके हैं। क्रायोजेनिक रॉकेट टेक्नोलॉजी, विकास और इनोवेशन के नए द्वार खोल रही है। भारत दुनिया के बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन चुका है।
- **ईको-फ्रेंडली जीवन:** आज देशवासियों में ईको-फ्रेंडली लाइफ को लेकर ज्यादा जागरूकता देखने को मिल रही है। कर्नाटक स्थित बेंगलुरू के सुरेश कुमार ने 20 साल पहले पौधारोपण कर सहकारनगर के जंगल का कायाकल्प किया। तमिलनाडु के अनाइकट्टी, कोयंबटूर की आदिवासी महिलाओं की एक टीम ने निर्यात के लिए 10 हजार इको-फ्रेंडली टेराकोटा चाय के कप तैयार किए। त्रिपुरा के कुछ गांव बायो-विलेज-2 के स्तर पर हैं।
- **टेकेड और भारत:** यह दशक भारत की तकनीक का है। देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उन्हें हल करने के लिए देश का युवा हैकथॉन के माध्यम से अभूतपूर्व गति से काम कर रहा है। इस महीने 23 आईआईटी अपने इनोवेशन और अनुसंधान परियोजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक साथ सामने आए। आईआईटी भुवनेश्वर की टीम ने पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया है जिसका उपयोग दूरस्थ क्षेत्रों में समय से पहले शिशुओं के जीवन को बचाने के लिए किया जा सकता है। आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर ने स्वदेशी रूप से विकसित 5जी टेस्टबेड को विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभाई है।

‘मन की बात’ पूरी सुनने के लिए QR कोड Scan करें

न्यू इंडिया
समाचार

वर्ष: 03, अंक: 10 | 16-30 नवंबर, 2022

प्रधान संपादक
सत्येन्द्र प्रकाश,
प्रधान महानिदेशक
पत्र सूचना कार्यालय , नई दिल्ली

वरिष्ठ सलाहकार संपादक
संतोष कुमार

वरिष्ठ सहायक सलाहकार संपादक
विभोर शर्मा
सहायक सलाहकार संपादक
अखिलेश कुमार
चन्दन कुमार चौधरी

भाषा संपादन
सुमित कुमार (अंग्रेजी)
जय प्रकाश गुप्ता (अंग्रेजी)
नदीम अहमद (उर्दू)
पॉलमी रक्षित (बंगाली)

सीनियर डिजाइनर
श्याम शंकर तिवारी
रविन्द्र कुमार शर्मा
डिजाइनर
दिव्या तलवार, अभय गुप्ता

13 भाषाओं में उपलब्ध न्यू इंडिया समाचार को पढ़ने के लिए क्लिक करें।
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx
न्यू इंडिया समाचार के पुराने अंक पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://newindiasamachar.pib.gov.in/archive.aspx

'न्यू इंडिया समाचार' के बारे में लगातार अपडेट के लिए फॉलो करें:- @NISPIBIndia

अंदर के पन्नों पर

स्वयं सहायता समूह बने राष्ट्र सहायता समूह

आवरण कथा

कहानी नारीशक्ति को नई पहचान मिलने की, उनके स्वावलंबन की, उन छोटे-छोटे समूहों की जो बनें राष्ट्र के विकास में सहायक और जिन्होंने बदली समाज की तस्वीर। 14-25

भक्ति-शक्ति की दीपावली

अयोध्या में दीपोत्सव और कारगिल में सेना के जवानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मनाई दीपावली। 12-13

जिन्होंने ने दी 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' को मजबूती

आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत पढ़िए उन नायकों की कहानी जिनके सपनों से मिल रहा एक भारत-श्रेष्ठ भारत को बल। 45-48

समाचार सार। 4-5

जिन्होंने हमें स्वावलंबन को जीना सिखाया
व्यक्तित्व में पढ़िए श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन की कहानी । 6-7

हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा है
संविधान दिवस पर पीएम मोदी के भाषणों पर आधारित विशेष आलेख। 8-10

विरासत पर गर्व, विकास के लिए हर संभव प्रयास
उत्तराखंड को विकास की सौगात । 11

प्रगति भी, प्रकृति भी
गुजरात में डिफेंस एक्सपो और लाइफ कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन। 26-29

मेक इन इंडिया, मेक फॉर द ग्लोब की दिशा में मील का पत्थर
प्रधानमंत्री मोदी ने वडोदरा में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का किया शिलान्यास । 30-31

एक भारत, श्रेष्ठ भारत की ओर बढ़ते कदम...
राष्ट्रीय एकता दिवस: केवड़िया में पीएम मोदी ने दी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि । 32-33

मिला सपनों का घर, खुला गरिमा का द्वार
फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत इस बार पीएम आवास योजना की सफलता की कहानी । 34-37

विशेष स्वच्छता अभियान 2.0
सरकारी दफ्तरों में फाइलों का अंबार खत्म, 88 लाख वर्गफीट से अधिक जगह खाली ।38-40

ई-रुपी होलसेल लांच
होलसेल ई-रुपी लांच, रिटेल जल्द । 41

स्थानीय हितों के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान
90वीं इंटरपोल महासभा में पीएम मोदी का संबोधन। 42-43

सहकारी संघवाद को मजबूती
गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में पीएम मोदी का संबोधन। 44

प्रकाशक और मुद्रक- मनीष देसाई , महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो **मुद्रण:** इनफिनिटी एडवर्टाइजिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, एफबीडी वन कॉर्पोरेट पार्क, 10वीं मंजिल, नई दिल्ली-फरीदाबाद बॉर्डर, एनएच-1, फरीदाबाद-121003। **पत्राचार और ईमेल के लिए पता:** कमरा संख्या-278, केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना भवन, द्वितीय तल, नई दिल्ली- 110003। **ईमेल-** response-nis@pib.gov.in आर. एन. आई. नंबर DELHIN/2020/78812

संपादक की कलम से...

नारी शक्ति के सामर्थ्य की कहानी

सादर नमस्कार।

आत्मनिर्भरता जब स्वयं से आगे बढ़ती है तो वह राष्ट्र का मिशन बन जाती है। अवसरों का सृजन कर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने की दिशा में पहल बन चुकी दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय आजीविका मिशन (DAY-NRLM) इसी की मिसाल बनी है। यह करोड़ों ग्रामीण परिवारों की आजीविका और आय का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। जिसने नारी शक्ति को एक नई पहचान और दिशा दी है। गांवों में खेती हो, पशुपालन का काम हो, डिजिटल सेवाएं हों, शिक्षा हो, बैंकिंग सेवाएं हों, बीमा से जुड़ी सेवाएं हों, मार्केटिंग हो, पोषण हो, अधिक से अधिक क्षेत्रों में महिलाओं-लड़कियों को प्रबंधन से जोड़ा जा रहा है जिसमें दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय आजीविका मिशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

राष्ट्र पर आई कोविड जैसी वैश्विक आपदा हो और तिरंगा फहराने का उत्सव या फिर सरकारी योजनाओं में भागीदारी के साथ-साथ उसकी निगरानी, अपने सामर्थ्य और संकल्प के कारण स्वयं सहायता समूह सही अर्थ में राष्ट्र सहायता समूह बन गए हैं। देश में लगभग 80 लाख स्वयं सहायता समूहों में 8.6 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं, जो स्वयं के साथ राष्ट्र की सहायता में जुटी हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों का यही सामर्थ्य आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाला है। राष्ट्र का मिशन बना आजीविका मिशन ही हमारी इस बार की आवरण कथा बनी है। 26 नवंबर हमारे इतिहास की ऐसी तारीख है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में एक नई शुरुआत दी। देश ने संविधान को अंगीकार करने की इस तिथि को 'संविधान दिवस' के रुप में मनाना शुरू किया। हमारे इस अंक में संविधान दिवस को समर्पित प्रधानमंत्री मोदी का एक विशेष आलेख भी है जो उनके भाषणों पर आधारित है। व्यक्तित्व की कड़ी में इस बार श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को राष्ट्र का नमन शामिल है जिनके प्रयासों से भारत दुग्ध उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है।

अपना मकान, हर किसी का सपना होता है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी-ग्रामीण) मील का पत्थर बन गई है। इस योजना की वर्षगांठ और आवास उत्सव के अवसर पर उसकी सफलता, अमृत महोत्सव की श्रृंखला में वीर नायकों की प्रेरक गाथा, मन की बात, प्रधानमंत्री मोदी की भक्ति और शक्ति वाली दिवाली के साथ ही पखवाड़े भर में प्रधानमंत्री की ओर से राष्ट्र को समर्पित परियोजनाएं इस अंक में शामिल हैं।

आप अपने सुझाव हमें भेजते रहें।

हिंदी, अंग्रेजी व अन्य 11 भाषाओं में उपलब्ध पत्रिका पढ़ें/डाउनलोड करें।
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

स.प्रकाश

आपकी बात...

महसूस हो रहा भारत माता पर गर्व

मुझे न्यू इंडिया समाचार पत्रिका का 1-15 अक्टूबर का अंक अच्छा लगा। पिछले तीन साल से इस पत्रिका को पढ़ कर मुझे भारत माता पर गर्व महसूस हो रहा है। देश भले ही 75 साल पहले आजाद हुआ था, लेकिन विकास के मामले में पिछड़ रहा था। पिछले आठ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विकास के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। इस कड़ी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केदारनाथ में निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण, श्री महाकाल कॉरिडोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की स्थापना, भारतीय नौसेना को आईएनएस विक्रांत सौंपने जैसे कई गौरवपूर्ण कार्य हैं। इसे पूरा देश हमेशा याद रखेगा। -सुष्मिता सबुई susmitasabui221@gmail.com

कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी

न्यू इंडिया समाचार देश की एकमात्र ऐसी पत्रिका है जो हमें देशहित मे भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देती है। यह पत्रिका हमें बहुत पसंद है। पत्रिका बेहतरीन तरीके से ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ प्रकाशित की जा रही है जो सराहनीय है। न्यू इंडिया समाचार पत्रिका अपने आप में एक संपूर्ण पत्रिका है।

teekshandrishti@gmail.com

पत्रिका मिलने की बहुत खुशी

मुझे 'न्यू इंडिया समाचार' पत्रिका मिलती रहती है, जिसकी मुझे बहुत ही खुशी हैं। इसका प्रकाशन बहुत ही उच्च दर्जे का और लेख पठनीय होते हैं। इसमें भारत की प्रगति से संबंधित जानकारी प्रकाशित की जाती है जो अच्छी लगती है। कवर और अमृत श्रृंखला की कहानी अच्छी लगी।

आनंद ताराचंद शर्मा

anandzmpress@gmail.com

अगले अंक का रहता है इंतजार

मुझे लंबे समय से ई मेल पर न्यू इंडिया समाचार पत्रिका मिल रही है। मैं पत्रिका का ताजा अंक पढ़ने के बाद अगले अंक का इंतजार करती हूं। यह पत्रिका जानकारी से परिपूर्ण रहती है। पत्रिका का नवीनतम अंक पढ़ कर मुझे इस बात का गर्व हुआ कि सरकार हमारे स्वदेशी उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करती है।

गीता एस

geetha.sarma@gmail.com

उच्च गुणवत्तापूर्ण पत्रिका के लिए धन्यवाद

न्यू इंडिया समाचार का ताजा अंक ई मेल पर प्राप्त हुआ। पत्रिका के संपादक और पूरी टीम को एक सजग सकारात्मक और उच्च गुणवत्तापूर्ण पत्रिका प्रकाशित करने के लिए धन्यवाद।

समीर मुले

ssmuley2007@rediffmail.com

हमें फॉलो करें @NISPIBIndia

पत्राचार और ईमेल के लिए पता: कमरा संख्या-278, केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना भवन, द्वितीय तल, नई दिल्ली- 110003। ईमेल- response-nis@pib.gov.in

रोजगार मेला

10 लाख कर्मियों की भर्ती का अभियान शुरु

न्यू इंडिया के विकास को गति देने में जुटे युवाओं को सरकार अधिक से अधिक स्व रोजगार और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर को नवनियुक्त 75 हजार कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने वाले रोजगार मेले का उद्घाटन कर एक नये युग की शुरुआत की। 12 महीनों में 10 लाख नौकरियां प्रदान करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है क्योंकि आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव को देखते हुए सरकार अगले 12 महीने तक, हर महीने 75 हजार नौकरी देगी।

यह भर्तियां मिशन मोड में मंत्रालयों और विभागों द्वारा अलग-अलग एजेंसी के माध्यम से की जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, "हमने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति-पत्र देने की परंपरा शुरू की जाए ताकि लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का सामूहिक स्वभाव और प्रयास विभागों में विकसित हो।"

प्रधानमंत्री मोदी ने नवनियुक्त युवाओं से आग्रह किया है कि "21वीं सदी के भारत में सरकारी सेवा, एक समय सीमा के भीतर लोगों को सेवा मुहैया कराने के प्रति एक वचनबद्धता है। आप जब भी कार्यालय में प्रवेश करें तो हमेशा अपने 'कर्तव्य पथ' को ध्यान में रखें।"

एडवेंचर से भरपूर होगा सिक्किम का 14 सुरंगों वाला रेल नेटवर्क, 58 फीसदी काम पूरा

पूर्वोत्तर के आठ राज्य आजादी के बाद 2014 तक विकास की दौड़ में पीछे ही रहे क्योंकि सड़क, रेल और हवाई संपर्क बनाने में अनदेखी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली और इस अष्टलक्ष्मी के विकास और कनेक्टिविटी की परियोजनाओं पर काम तेजी से हो इसलिए खुद निगरानी शुरू की। रेल नेटवर्क का संपर्क यहां के 7 राज्यों में है जबकि आठवें राज्य सिक्किम के लिए नई रेल लाइन परियोजना सिवोक-रंगपो (45 किलोमीटर) पर काम तेज गति से चल रहा है, जो एडवेंचर से भरपूर होगा। नई रेल लाइन पश्चिम बंगाल के सिवोक से सिक्किम के रंगपो तक बन रही है। इसमें करीब 86% हिस्से में 14 सुरंगें बन रही हैं। सुरंगों के 58% हिस्से में खुदाई का काम पूरा हो गया है तो 13 बड़े पुलों का 42% काम पूरा हो गया है। इस सेक्शन में सबसे लंबी सुरंग 5.30 किलोमीटर और सबसे छोटी सुरंग 538 मीटर की है। इस रेलवे लाइन पर सिवोक और रंगपो सहित पांच स्टेशनों का निर्माण होना है जिसमें सिवोक, रियांग, मेली और रंगपो खुले में होंगे जबकि एक भूमिगत हॉल्ट स्टेशन तीस्ता बाजार बनाने का प्रस्ताव है। यह रेल लाइन इलाके को नया जीवन देने वाली है, यह सफर दो घंटे से भी कम समय में पूरा होगा। इसके बाद जहां पर्यटन और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, वहीं सामरिक दृष्टिकोण से भी यह परियोजना महत्वपूर्ण साबित होगी क्योंकि मौजूदा समय में दूसरे राज्यों से सिक्किम को जोड़ने के लिए एनएच-10 ही एकमात्र सड़क है।

लोथल में दिखेगी देशभर की समुद्री विरासत

गुजरात का लोथल हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक था। यह सबसे पुराने मानव निर्मित डॉकयार्ड की खोज के लिए जाना जाता है। भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत रही है। देश में 'अपनी विरासत के प्रति गर्व' की भावना के संकल्प को मजबूती देने के लिए लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित किया जा रहा है। करीब 3500 करोड़ रुपये की लागत वाले इस परिसर में हड़प्पा की वास्तुकला, लोथल मिनी रीक्रिएशन, चार थीम पार्क, दुनिया का सबसे ऊंचा लाइटहाउस संग्रहालय, हड़प्पा काल से लेकर आज तक भारत की समुद्री विरासत पेश करने वाली चौदह दीर्घाएं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने वाला तटीय राज्यों का एक पैवेलियन भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 अक्टूबर को निर्माण कार्यों की समीक्षा के बाद कहा, "जब हम अपनी विरासत को संजोते हैं तो हम उससे जुड़ी भावनाओं को संरक्षित करते हैं। पिछले 8 वर्षों में विकसित की गई विरासत हमें भारत के विरासत की विशालता की झलक दिखाती है।"

भारत के दो और समुद्र तटों को मिला ब्लू फ्लैग, सूची में 12 समुद्री तट शामिल

देश में समुद्र तट पर्यावरण और सौंदर्य प्रबंधन सेवा (BEAMS) कार्यक्रम के तहत ब्लू फ्लैग समुद्र तट प्रमाण पत्र के लिए समुद्र तटों पर किए जाने वाले प्रदूषण उपशमन, सौंदर्यीकरण, सुरक्षा, पर्यावरण शिक्षा और जागरुकता कार्यकलाप का नतीजा है कि दुनिया के सबसे साफ समुद्र तटों की ब्लू बीच सूची में भारत के 2 और समुद्र तटों ने जगह बनाई है। अब ब्लू बीच सूची में भारतीय बीच की संख्या 12 हो गई है। यह दोनों समुद्र तट मिनिकॉय, थुंडी बीच और कदमत बीच लक्षद्वीप में हैं। ब्लू फ्लैग दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों को दिया गया एक अंतरराष्ट्रीय इको-लेबल है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट किया, "गर्व का क्षण! यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक स्थायी वातावरण बनाने की दिशा में भारत की अथक यात्रा का हिस्सा है। थुंडी बीच लक्षद्वीप द्वीपसमूह में सबसे प्राचीन और सुरम्य समुद्र तटों में से एक है, जहां लैगून के फिरोजा नीले पानी से सफेद रेत घिरी हुई है, कदमत समुद्र तट विशेष रूप से क्रूज पर्यटकों के लिए लोकप्रिय है जो वॉटर स्पोर्ट्स के लिए द्वीप पर आते हैं।"

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता अंतरिक्ष क्षेत्रः दुनिया ने देखा न्यू इंडिया का सामर्थ्य

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया ने 23 अक्टूबर को अंतरिक्ष क्षेत्र में न्यू इंडिया का सामर्थ्य देखा जब इसरो ने अब तक के सबसे भारी रॉकेट LVM3 के जरिये वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए 36 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर नया इतिहास रचा। इसरो की तरफ से कक्षा में स्थापित किए जाने वाले विदेशी उपग्रहों की संख्या अब 381 पहुंच गई है। यह LVM3 का पहला कॉमर्शियल लांच है। यह रॉकेट 43.5 मीटर लंबा और 644 टन वजनी है, जो 8 हजार किलो वजन ले जाने में सक्षम है। वनवेब, भारत की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और यूके सरकार का ज्वाइंट वेंचर है जिसने पहली बार अपने उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए भारतीय रॉकेट का उपयोग किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, "वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए 36 वन वेब सैटेलाइट्स के साथ हमारे सबसे भारी प्रक्षेपण यान एलवीएम3 के सफल प्रक्षेपण पर एनएसआईएल, इन-स्पेस और इसरो को बधाई। एलवीएम3 आत्मनिर्भरता की अनूठी मिसाल है और वैश्विक कमर्शियल लॉन्च सेवा बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को ये बढ़ाता है।" ●

श्वेत क्रांति के जनक

जिन्होंने हमें स्वावलंबन को जीना सिखाया

जन्म: 26 नवंबर 1921। मृत्यु: 9 सितंबर 2012

आजादी के अमृत काल में जब देश आत्मनिर्भरता के रास्ते विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की ओर बढ़ रहा है, तब यह कालखंड उन महान व्यक्तित्वों को नमन करने का भी है जिन्होंने हमें गुलामी के कालखंड से निकाल कर स्वावलंबन का पाठ ही नहीं पढ़ाया, बल्कि उसे जीना भी सिखाया। ऐसी ही एक शख्सियत हैं, वर्गीज कुरियन, जिन्होंने उस वक्त श्वेत क्रांति की परिकल्पना की। कभी दूसरों से दूध मांग कर अपनी जरूरतें पूरी करने वाला भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। इसके पीछे वर्गीज कुरियन की उस सोच का ही कमाल है, जिसने अमूल जैसी सहकारी संस्था का सर्वश्रेष्ठ मॉडल दुनिया के सामने किया पेश...

जब आप सुबह अपने हाथों में चाय का कप लिए होते हैं या फिर रात को दूध का गिलास, तब अनायास ही सही पर भारत में स्वावलंबन के उस सबसे बड़े आंदोलन में अपना योगदान दे रहे होते हैं, जो न सिर्फ सहकारिता की एक इतिहासगाथा अपने भीतर समेटे हुए है, बल्कि इसकी बदौलत ही भारत दूध के वैश्विक बाजार में 21 फीसदी की भागीदारी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है। ये कमाल है श्वेत क्रांति का और इस क्रांति के नायक हैं वर्गीज कुरियन और त्रिभुवन दास। केरल के कोझीकोड में 26 नवंबर 1921 को एक सिविल सर्जन के घर जन्म लेने वाले वर्गीज कुरियन ने मद्रास विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद वे सरकारी स्कॉलरशिप पर पोस्ट ग्रेजुएशन करने अमेरिका के मिशीगन विश्वविद्यालय गए। तब इस स्कॉलरशिप के बदले शर्त थी कि उन्हें देश लौटकर कम से कम 3 साल सरकारी संस्था में काम करना होगा। उनकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक विषय डेयरी इंजीनियरिंग भी था।

इसी समय आजादी से ठीक पहले 1946 में गुजरात के खेड़ा में दुग्ध उत्पादक किसान अंग्रेज सरकार के खिलाफ सरदार वल्लभभाई पटेल की सलाह पर आंदोलन कर रहे थे। क्योंकि तब यहां एक कंपनी पोल्सन के पास ही दूध खरीदने का अधिकार था। खेड़ा और आणंद तब गुजरात के कैरा जिले का हिस्सा हुआ करता था। कंपनी यहां मनमाने दामों पर दूध खरीदती और फटेहाल किसानों के हाथ कुछ न आता। सरदार पटेल ने सलाह दी, सहकारी समिति बनाओ और ब्रिटिश सरकार से पॉश्चर प्लांट लगाने की अनुमित मांगो। अनुमति न मिले तो एक बूंद भी दूध न बेचो। सरकार को झुकना पड़ा और इस तरह कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ का जन्म हुआ। त्रिभुवनदास पटेल इसके प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए। दो गांवों और रोज औसत 250 लीटर दूध के साथ कारोबार शुरू हुआ।

यह समिति अपने शैशवकाल में ही थी कि ठीक उसी वक्त यहां के एक सरकारी क्रीमरी कारखाने में अमेरिका से पढ़कर लौटे डॉ. वर्गीज कुरियन का आगमन हुआ। कुरियन त्रिभुवन दास के संपर्क में आए। कई मुलाकातों के बाद उनकी अच्छी जान पहचान हो गई। कोऑपरेटिव डेयरी के कई मामलों में कुरियन उनकी मदद करते रहते। 1949 में किसानों की कोऑपरेटिव डेयरी में नया प्लांट लगाने में भी उन्होंने मदद की थी। हालांकि, वर्गीज कुरियन का यहां मन नहीं लग रहा था और उन्होंने सरकार से कई बार उन्हें किसी शहर में पोस्टिंग देने की गुजारिश की। 1949 के अंत तक सरकार ने उनकी मांग मान ली। वे खेड़ा से

जाने की तैयारी करने लगे। ये बात जब त्रिभुवन दास पटेल को पता लगी तो वे किसानों के साथ तुरंत वर्गीज कुरियन के पास पहुंचे। डॉ. कुरियन ने काफी विचार-विमर्श के बाद 'खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन' के साथ जुड़ने का फैसला कर लिया और 1 जनवरी 1950 को वह बतौर मैनेजर जुड़ गए। मैनेजर के रूप में वर्गीज कुरियन के सामने सबसे बड़ी चुनौती दूध उत्पादक किसानों की बढ़ती संख्या थी। लगातार जुड़ते किसानों के साथ तब दूध की इतनी आवक थी कि इसकी खपत नहीं हो पा रही थी। उस समय तक यूरोप और न्यूजीलैंड में अधिक दूध होने पर उसे खपाने के लिए मिल्क पाउडर बनाया जाता था। यूरोप और न्यूजीलैंड वालों का कहना था कि केवल गाय के दूध का ही पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क बन सकता है लेकिन कुरियन और उनके दोस्त व साथी एचएम दलाया ने भैंस के दूध से स्किम दूध पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क बनाकर दुनिया को चौंका दिया। किसानों के पारंपरिक कौशल और अनुभवजन्य ज्ञान के साथ कुरियन की आधुनिक शिक्षा और तकनीक ने कमाल कर दिया। समिति में अब मक्खन और क्रीम से लेकर पनीर तक बनाया जाने लगा था। 1955 में जब कोऑपरेटिव डेयरी के ब्रांड का नाम रखने की बारी आई तो डॉ. कुरियन ने इसका नाम अमूल (आणंद मिल्क यूनियन लिमिटेड) रखा। 1956 में अमूल रोजाना 1 लाख लीटर दूध प्रोसेस करने लगा। अब गुजरात से अमूल के उत्पाद अन्य राज्यों में भी जाने लगे थे। उत्पादन बढ़ा तो डॉ. कुरियन ने खेड़ा में जानवरों के चारे और आहार के लिए एक प्लांट लगाया। तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इसके उद्घाटन के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने दूध उत्पादकों की संपन्नता को देखा तो हैरान रह गए। लाल बहादुर शास्त्री ने खेड़ा का मॉडल पूरे देश में लागू करने के लिए कुरियन से प्लान बनाकर दिल्ली आने को कहा। इस तरह 1965 में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) स्थापित किया गया, जिसका कार्य आंणद की तर्ज पर देशभर में सहकारी दुग्ध समितियां तथा संघ गठित करना था। कुरियन बोर्ड के अध्यक्ष बने। 1969 में जब भारत सरकार ने देश में डेयरी उद्योग के विकास के लिए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की घोषणा की, तब सरकारी संसाधनों के सुचारू वितरण के लिए एक सरकारी क्षेत्र की कंपनी की आवश्यकता महसूस हुई। इस प्रकार 1970 में भारतीय डेयरी निगम (आईडीसी) अस्तित्व में आया। अक्टूबर 1987 में एनडीडीबी को पुनर्गठित करते हुए आईडीसी को इसी में ही समाहित कर दिया गया। 'ऑपरेशन फ्लड' को तीन फेज में लागू किया गया। पहले फेज में डॉ. कुरियन ने देश भर में करीब 13 डेयरी प्लांट बनाए और एक पशु आहार प्लांट स्थापित किया। दूसरा फेज 1980 से शुरू हुआ और 1990 तक चला। इसमें उन्होंने देश भर में करीब 170 डेयरी प्लांट और 32 पशु आहार प्लांट लगाए। फिर आया 'ऑपरेशन फ्लड' का तीसरा और अंतिम फेज जो 1990 से शुरू हुआ। इस दौरान उन प्लांट्स यानी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की पहचान की गई, जो सही से काम नहीं कर पा रहे थे। अलग से फंड लगाकर इनकी स्थिति को बेहतर किया गया। इस दौरान देशभर में लोगों तक दूध की पहुंच आसान बनाने के लिए दूध की वेंडिंग मशीनें लगाई गईं। दुकानों पर दूध के बड़े-बड़े कंटेनर लगवाए गए। 1997 में 'ऑपरेशन फ्लड' पूरा हो गया। इसकी मदद से भारत के 700 से ज्यादा शहरों में अच्छी क्वालिटी का दूध सही दामों में पहुंचाने में मदद मिली तो साथ ही भारत का पशुपालन क्षेत्र भी आय का एक प्रमुख स्रोत बन पाया।

ऑपरेशन फ्लड के दौरान ही भारत दूध की कमी वाले देशों की लिस्ट से निकलकर दूध के बड़े उत्पादक देशों में शामिल हो गया। 1998 में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला देश बन गया। इसके बाद दुनिया ने वर्गीज कुरियन को सफेद क्रांति का जनक कहा। 1951 में 17 मिलिटन टन वार्षिक दूध उत्पादन से शुरू हुआ सफर 2021 में 209.96 मिलियन टन पहुंच गया है। उन्हें भारत सरकार ने 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उन्हें रैमन मैगसेसे और वर्ल्ड फूड प्राइज जैसे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। भारत की श्वेत क्रांति में उनके योगदान को याद करने के लिए 26 नवंबर को उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। साल 2012 में 90 साल की उम्र में वर्गीज कुरियन का देहांत हो गया। ●

"हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा है"

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

भारतीय संविधान को 73 वर्ष पूर्व अंगीकार किया गया था, लेकिन संविधान दिवस मनाने की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में की। देश इस 26 नवंबर को जब 8वां संविधान दिवस मना रहा है तो इसकी महत्ता पर प्रधानमंत्री मोदी के विचारों को जानते हैं, जिसे उन्होंने कई अलग-अलग अवसरों पर साझा किया है ...

कुछ दिन और कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो अतीत के साथ हमारे संबंधों को मजबूती देते हैं। हमें बेहतर भविष्य और उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। 26 नवंबर का दिन ऐसा ही ऐतिहासिक है। लगभग 73 साल पहले हमने विधिवत रूप से एक नए रंग-रूप के साथ संविधान को अंगीकार किया था। सात दशक पहले संसद के सेंट्रल हॉल में पवित्र आवाजों की गूंज थी, संविधान के एक-एक अनुच्छेद पर बारीकी से गहन चर्चा हुई। तर्क आए, तथ्य आए, विचार आए, आस्था की चर्चा हुई, विश्वास की चर्चा हुई, सपनों की चर्चा हुई, संकल्पों की चर्चा हुई। एक प्रकार से संसद का यह केंद्रीय कक्ष ज्ञान का महाकुंभ था, जहां पर भारत के हर कोने के सपनों को शब्दों में मढ़ने का एक भरपूर प्रयास हुआ था। डॉ. राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहर लाल नेहरू, आचार्य सुकराणी, मौलाना आजाद, पुरूषोत्तम दास टंडन, सुचेता कृपलानी, हंसा मेहता, एलडी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालास्वामी एंगर, जॉन मथाई अनगिनत ऐसे महापुरुष जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान देकर यह महान विरासत हमारे हाथों में सुपुर्द की है।

कभी हम सोचें कि आज अगर हमें संविधान निर्माण करने की नौबत होती तो क्या होता? आजादी के आंदोलन की छाया, देशभक्ति की ज्वाला, भारत विभाजन की विभीषिका इन सबके बावजूद भी देशहित सर्वोपरि, हर एक के हृदय में एक यही मंत्र था। विविधताओं से भरा हुआ यह देश, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, अनेक पंथ, अनेक राजे रजवाड़े इन सबके बावजूद भी संविधान के माध्यम से पूरे देश को एक बंधन में बांध कर आगे बढ़ाने के लिए योजना बनाना। आज के संदर्भ में देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते? उन महानुभावों को प्रणाम इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि उनके विचारों की भी अपनी धारा होगी। उस धारा में धार भी होगी। लेकिन फिर भी राष्ट्रहित सुप्रीम होने के नाते सबने मिल बैठकर एक संविधान दिया।

हमारा संविधान यह सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत

की महान परंपरा, अखंड धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। इसलिए जब हम इस संवैधानिक व्यवस्था के तहत जन प्रतिनिधि के रूप में ग्राम पंचायत से संसद तक का जो भी दायित्व निभाते हैं, उसमें हमें संविधान के लेटर एंड स्पिरिट के समर्पित भाव से खुद को सज्ज रखना होगा। जब ये करते है तो संविधान की भावनाओं को कहां चोट पहुंच रही है उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस संविधान दिवस को हमें इसलिए भी मनाना चाहिए, क्योंकि यह हमें इस बात का मूल्यांकन करने का अवसर देता है कि हमारा जो रास्ता है, वह सही है या नहीं है। हर वर्ष संविधान दिवस मनाकर हमें अपने आप का मूल्यांकन करना चाहिए। देश आजाद होने और 26 जनवरी प्रजासत्ता पर्व की शुरुआत के बाद से ही हमें 26 नवंबर को संविधान दिवस के रुप में मनाने की परंपरा बनानी चाहिए थी। ताकि उसके कारण हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी संविधान बना कैसे? इसे बनाने वाले कौन लोग थे? किन परिस्थितियों में बना? क्यों बना? हमे संविधान कहां ले जाता है? कैसे ले जाता है? इन सारी बातों की हर वर्ष अगर चर्चा होती है, तो संविधान जिसको दुनिया ने एक जीवंत इकाई और एक सामाजिक दस्तावेज के रुप में माना है, विविधता भरे देश के लिए यह एक बहुत बड़ी ताकत और अवसर के रुप में पीढ़ी दर पीढ़ी काम आता। ऐसा करने से कुछ लोग चूक गए। लेकिन जब 26 नवंबर 2015 को बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं जयंती थी तब इस पवित्र अवसर पर देशभर में संविधान दिवस माने की शुरुआत सरकार ने की।

आज अगर बाबा साहेब होते तो उनसे अधिक प्रसन्नता शायद ही किसी को होती। क्योंकि भारत ने इतने वर्षों में न केवल उनके सवालों का उत्तर दिया है बल्कि अपनी आजादी और लोकतंत्र को और अधिक समृद्ध और सशक्त किया है। इसलिए संविधान दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को बीते सात दशक में संविधान की भावना को अक्षुण्ण रखने वाली विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के सभी साथियों को गौरवपूर्वक स्मरण करता हूं, नमन करता हूं। मैं विशेष तौर पर 130 करोड़ भारतवासियों के सामने नतमस्तक हूं, जिन्होंने भारत के लोकतंत्र के प्रति आस्था को कभी कम नहीं होने दिया। हमारे संविधान को हमेशा एक पवित्र ग्रंथ माना, गाइडिंग लाइट माना।

संविधान के 73 वर्ष हमारे लिए हर्ष, उत्कर्ष और निष्कर्ष का मिला-जुला भाव लेकर आए हैं। हर्ष ये है कि संविधान की भावना अटल और अडिग रही है। अगर कभी कुछ इस तरह के प्रयास हुए भी हैं तो देशवासियों ने मिलकर उनको असफल किया है। संविधान पर आंच नहीं आने दी है। हमारे संविधान की मजबूती के कारण ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ हम आगे बढ़ पाए हैं। हमने तमाम सुधार मिल-जुलकर संविधान के दायरे में रहकर किए हैं। निष्कर्ष यह है कि यह विशाल और विविधता से भरा भारत प्रगति के लिए, सुनहरे भविष्य और नए भारत के लिए भी, हमारे सामने सिर्फ संविधान, संविधान की मर्यादाएं, संविधान की भावना यही एकमात्र रास्ता है-एषपंथा। हमारा संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा और पवित्र ग्रंथ है। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें हमारे जीवन की, हमारे समाज की, हमारी परंपराओं, हमारी मान्यताओं, हमारे व्यवहार, हमारे आचार उन सबके साथ का समावेश है। साथ-साथ अनेक चुनौतियों का समाधान भी है। हमारा संविधान इतना व्यापक इसलिए है क्योंकि इसमें हमने बाहरी प्रकाश के लिए अपनी खिड़कियां खोल रखी हैं। उसके साथ-साथ भीतर का जो प्रकाश है उसको और अधिक प्रज्ज्वलित करने का अवसर भी दिया है।

बाबा साहेब अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949, संविधान अंगीकार करने के एक दिन पूर्व अपने आखिरी भाषण में जो बातें कही थी उसका जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। बाबा साहेब ने देश को याद दिलाया था कि भारत पहली बार 1947 में आजाद हुआ है या फिर 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना, ऐसा नहीं है। भारत पहले भी आजाद था और हमारे यहां अनेक रिपब्लिक भी थे। उन्होंने आगे व्यथा व्यक्त की थी कि अपनी ही गलतियों से हमने अतीत में आजादी भी खोई है और रिपब्लिक कैरेक्टर भी गंवाया है। ऐसे में बाबा साहेब ने देश को चेताते हुए पूछा था कि हमें आजादी भी मिल गई, गणतंत्र भी हो गए, लेकिन क्या हम इसको बनाए रख सकते हैं? क्या अतीत से हम सबक ले सकते हैं?

एक बात 2014 में लाल किले के प्राचीर से जो मैने कही थी उसको दोहराऊंगा, संविधान को अगर दो सरल शब्दों में कहना है तो कहूंगा 'डिगनीटि फॉर इंडियन एंड यूनिटी फॉर इंडिया' इन्ही दो मंत्रों को हमारे संविधान ने साकार किया है। नागरिक की डिगनीटि को सर्वोच्च रखा है और संपूर्ण भारत की एकता और अंखडता को अक्षुण्ण रखा है। हमारा संविधान वैश्विक लोकतंत्र की सर्वोच्च उपलब्धि है। यह न केवल अधिकारों के प्रति सजग है बल्कि हमारे कर्त्तव्यों के प्रति हमें जागरूक भी बनाता है। एक दृष्टि से हमारा संविधान दुनिया में सबसे अधिक पंथनिरपेक्ष है। हमें क्या करना है, कितने बड़े सपने देखने हैं और कहां तक पहुंचना है इसके लिए किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं है। संविधान में ही अधिकार की बात है और संविधान में ही कर्त्तव्यों के पालन की अपेक्षा है। क्या हम एक व्यक्ति, एक परिवार और एक समाज के तौर पर अपने कर्त्तव्यों को लेकर उतने ही गंभीर हैं जितना की हमारा संविधान, हमारा देश, हमारे देशवासियों के सपने हमसे अपेक्षा करते हैं। जैसा कि राजेंद्र बाबू ने कहा था कि जो संविधान में लिखा नहीं है उसको हमें कन्वेन्शन से स्थापित करना होगा और यही भारत की विशेषता भी है। बीते दशकों में हमने अपने अधिकारों पर बल दिया जो आवश्यक भी था और ठीक भी था। क्योंकि समाज में ऐसी व्यवस्थाएं बन गई हैं जिनके चलते एक बड़े वर्ग को अधिकारों से वंचित रखा गया था। बिना अधिकारों से परिचय कराए इस बड़े वर्ग को समानता, समता और न्याय का अहसास दिला पाना संभव नहीं था। लेकिन आज समय की मांग है कि जब हमें अधिकारों के साथ ही एक नागरिक के तौर पर अपने कर्त्तव्यों, अपने दायित्व पर मंथन करना ही होगा। क्योंकि दायित्व को निभाए बिना हम अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। एक नागरिक जब अपने बच्चे को स्कूल भेजता है तो मां-बाप अपना कर्तव्य निभाते हैं लेकिन वह मां-बाप जागरूकता पूर्वक अपने बच्चे को मातृभाषा सीखने का आग्रह रखते हैं तो वे एक नागरिक का कर्तव्य निभाते हैं। देश सेवा का कर्तव्य निभाते हैं। अगर बूंद-बूंद पानी बचाता है वो अपना नागरिक कर्तव्य भी निभाता है।

यह आजादी के 75 साल हैं, यह अमृतकाल है। अंग्रेज भारत के नागिरकों के अधिकारों को कुचलने में लगे थे। हिन्दुस्तान के नागरिकों को उसके अधिकार मिले उसके लिए लड़ना बहुत स्वाभाविक और जरुरी भी था। महात्मा गांधी समेत हर कोई भारत के नागरिकों को उनके अधिकार मिले इसलिए वह लड़ते रहे यह बहुत स्वाभाविक है। यह भी सही है कि महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन में अधिकारों के लिए लड़ते-लड़ते भी, देश को कर्तव्य के लिए तैयार करने की लगातार कोशिश की थी। उन्होंने भारत के नागरिकों में उस बीज को बोने की लगातार कोशिश की थी। सफाई करो, प्रौढ़ शिक्षा करो, नारी सम्मान करो, नारी को सशक्त करो, खादी पहनो, स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर का विचार और कर्तव्यों की तरफ महात्मा गांधी लगातार देश को तैयार करते रहे। महात्मा गांधी ने जो कर्तव्यों के बीज बोए थे, वो आजादी के बाद वट वृक्ष बन जाने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से अधिकार की ही बातें कर लोगों को ऐसी व्यवस्था में रखा कि हम हैं तो अधिकार पूरे होंगे। अच्छा होता देश आजाद होने के बाद कर्तव्य पर बल दिया होता, तो अधिकारों की अपने आप रक्षा होती।

> **संविधान दिवस को इसलिए भी मनाना चाहिए, क्योंकि यह इस बात का मूल्यांकन करने का अवसर देता है कि हमारा जो रास्ता है, वह सही है या नहीं है।**
>
> **आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे लिए आवश्यक है कि कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ें ताकि अधिकारों की रक्षा हो।**

कर्तव्यों से दायित्व का बोध होता है, कर्तव्य से समाज के प्रति एक जिम्मेदारी का बोध होता है। अधिकार से कभी-कभी एक याचकवृत्ति पैदा होती है कि मुझे मेरा अधिकार मिलना चाहिए, यानी समाज को कुंठित करने की कोशिश होती है। कर्तव्य के भाव से सामान्य मानव के जीवन में एक भाव होता है कि यह मेरा दायित्व है मुझे इसको निभाना है। जब मैं कर्तव्य का पालन करता हूं तो अपने आप किसी न किसी के अधिकार की रक्षा हो जाती है। इस तरह कर्तव्य और अधिकार साथ-साथ चलते हैं और स्वस्थ समाज की रचना होती है।

आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम कर्तव्यों के माध्यम से अधिकारों की रक्षा करने के रास्ते पर चल पड़े। कर्तव्य वो पथ है जिसमें अधिकार की गारंटी है। कर्तव्य वो पथ है, जो अधिकार और सम्मान के साथ दूसरे को स्वीकृत करता है, उसको हक देता है। आज जब हम संविधान दिवस मना रहे हैं, तब हमारे भीतर भी यही भाव निरंतर जगता रहे कि हम कर्तव्य पथ पर चलते रहें। कर्तव्य को जितनी अधिक मात्रा में निष्ठा और तपस्या के साथ हम निभाएंगे, हर किसी के अधिकारों की रक्षा होगी। आजादी के दीवानों ने जिन सपनों को लेकर भारत को बनाया था उन सपनों को पूरा करने का सौभाग्य आज हम लोगों को मिला है। हम लोगों को मिलकर उन सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। ●

विरासत पर गर्व, विकास के लिए हर संभव प्रयास

उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से घिरा माणा भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव है। पहले देश का आखिरी गांव जानकर जिसकी उपेक्षा की जाती थी, अब वहां के लोगों की अपेक्षाओं पर फोकस किया गया है। साथ ही, प्रयास किया जा रहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में एक जीवंत जीवन हो जहां विकास का उत्सव मनाया जा सके। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अक्टूबर को माणा में 3,400 करोड़ रुपये से अधिक की सड़क और रोपवे परियोजनाओं की रखी आधारशिला...

21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं -अपनी विरासत पर गर्व और विकास के लिए हर संभव प्रयास। राष्ट्र आज इन दोनों स्तंभों को मजबूत कर रहा है। उत्तराखंड के अंतिम गांव के रूप में पहचान रखने वाले माणा में विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आस्था के ये केंद्र सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि हमारे लिए यह प्राणशक्ति है, प्राणवायु की तरह हैं। वो हमारे लिए ऐसे शक्तिपुंज हैं, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में हमें जीवंत बनाए रखते हैं। उनकी घोर उपेक्षा के बावजूद न तो हमारे आध्यात्मिक केंद्रों का महत्व कम हुआ, न ही उन्हें लेकर हमारे सपर्मण भाव में कोई कमी आई।" यही कारण है कि आज काशी, उज्जैन, आयोध्या और कई अन्य आध्यात्मिक केंद्र अपने खोए हुए गौरव एवं विरासत को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब अनेक सेवाओं को प्रौद्योगिकी से जोड़ते हुए आस्था को धारण कर रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर से गुजरात के पावागढ़ में मां कालिका मंदिर और देवी विंध्याचल कॉरिडोर तक, भारत अपने सांस्कृतिक और पारंपरिक उत्थान की घोषणा कर रहा है। इन आस्था स्थलों के कायाकल्प से जहां तीर्थयात्रियों को आसानी हो रही है वहीं बुजुर्गों को भी सुविधा हो रही है।

उत्तराखंड के माणा गांव में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास

- केदारनाथ में रोपवे लगभग 9.7 किलोमीटर लंबा होगा और गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा, जिससे दोनों स्थानों के बीच यात्रा का समय वर्तमान में 6-7 घंटे से घटकर केवल 30 मिनट रह जाएगा।
- हेमकुंड रोपवे, गोविंदघाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ेगा। यह लगभग 12.4 किलोमीटर लंबा होगा और यात्रा के समय को एक दिन से कम कर केवल 45 मिनट तक ही सीमित कर देगा। यह रोपवे घांघरिया को भी जोड़ेगा, जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है।
- लगभग 2430 करोड़ रुपये की कुल लागत से विकसित, रोपवे यात्रा को सुरक्षित, संरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए परिवहन का एक पर्यावरण के अनुकूल साधन होगा। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे।
- करीब एक हजार करोड़ रुपये की सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। दो सड़क चौड़ीकरण परियोजनाएं- माणा से माणा दर्रा और जोशीमठ से मलारी तक हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में हर मौसम के अनुकूल सड़क संपर्क प्रदान करने की दिशा में एक और कदम होगा। ●

भक्ति-शक्ति की दीपावली

भारत के लोग उस सभ्यता और संस्कृति के वाहक हैं जिनके जीवन में पर्व और उत्सव, सहज-स्वाभाविक हिस्सा रहे हैं। दीपावली का संबंध प्रकाश और आभा से है। दीपावली के दीपक, भारत के आदर्शों, मूल्यों और दर्शन के जीवंत ऊर्जापुंज हैं। दीप से दीपावली तक, यही भारत का दर्शन है, ऐसे ही दर्शन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां 23 अक्टूबर को अयोध्या में भक्ति भाव वाले भव्य दीपोत्सव समारोह की शुरुआत की, वहीं लोकतांत्रिक रूप से चुने गए सरकार के मुखिया के तौर पर पिछले 21 साल से शक्ति-सामर्थ्य से भरपूर सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने की अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए 24 अक्टूबर को करगिल में सैन्य बलों के साथ मनाई दिवाली...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेजर अमित की पहली मुलाकात 2001 में बलाचडी के एक सैनिक स्कूल में हुई। 24 अक्टूबर को वे एक बार फिर कारगिल में प्रधानमंत्री से मिले। मेजर अमित की यह मुलाकात काफी भावनात्मक थी।

इस बार दीपावली एक ऐसे समय में आई है, जब हमने कुछ समय पहले ही आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं और हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अयोध्या में इस वर्ष, दीपोत्सव का छठा संस्करण आयोजित किया गया और पहली बार था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समारोह में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया। दीपावली की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्रीरामलला विराजमान का दर्शन और पूजन किया और बाद में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उसी दिन अयोध्या में भगवान श्रीराम के प्रतीक स्वरूप का राज्याभिषेक किया और सरयू नदी के न्यू घाट पर आरती में भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री ने संतों से भी मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इसके बाद उन्होंने भव्य दीपोत्सव समारोह की शुरुआत की। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "जब श्रीराम का अभिषेक होता है, तो हमारे भीतर भगवान राम के आदर्श एवं मूल्य और दृढ़ हो जाते हैं। राम के अभिषेक के साथ ही उनका दिखाया पथ और प्रदीप्त हो उठता है। अयोध्या जी के कण-कण में हम उनके दर्शन को देखते हैं।" पीएम बनने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन्य बलों के साथ दिवाली मनाने की अपनी परंपरा बरकरार रखी है और बतौर पीएम जवानों के साथ लगातार 9वीं दिवाली मनाई। कारगिल में जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत हमेशा विश्व शांति के पक्ष में है। उन्होंने कहा, "हम युद्ध के विरोधी हैं, लेकिन सामर्थ्य के बिना शांति संभव नहीं है। हमारी सेनाओं के पास सामर्थ्य भी है, रणनीति भी है। अगर कोई हमारी तरफ नजर उठाकर देखेगा तो हमारी तीनों सेनाएं दुश्मन को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देना भी जानती हैं।" अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर 15 लाख से अधिक दीये जलाए गए। ●

ग्रामीण भारत की नई क्रांति

स्वयं सहायता समूह बने राष्ट्र सहायता समूह

अवसरों का सृजन कर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने की दिशा में पहल बन चुकी दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय आजीविका मिशन (DAY-NRLM) करोड़ों ग्रामीण परिवारों की आजीविका और आय का महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। इसने नारी शक्ति को एक नई पहचान और दिशा दी है। साथ ही, छोटे-छोटे समूहों के माध्यम से प्रशिक्षित, प्रेरित, मार्गदर्शित हुई महिलाएं स्वावलंबन की नई राह पर आगे बढ़कर बना रही हैं अपनी अलग पहचान और अब उनके कामकाज बन गए हैं राष्ट्र की सहायता का मिशन, जिससे मिल रही है आत्मनिर्भर भारत को गति...

आजीविका मिशन बन रहा
राष्ट्र का मिशन

34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में है स्वयं सहायता समूह का कवरेज।

721 जिलों में गतिविधियों का हो रहा आयोजन।

6,861
ब्लॉकों में इसके तहत कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है।

2,63,355
ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूहों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

7,15,390
गांवों में एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है।

> **"पहले मेरी कोई पहचान नहीं थी, अब कृषि सखी के नाम से मेरी अलग पहचान है। सभी लोग जैविक खेती खाद के बारे में आकर पूछते हैं और अन्य राज्यों से भी लोग फोन करके पूछते हैं।"**

आत्मविश्वास से लबरेज मध्य प्रदेश की चंपा सिंह का यह कहना है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय आजीविका मिशन की मदद से स्वयं सहायता समूह से जुड़कर न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई है, बल्कि आमदनी को छह-सात गुना बढ़ा लिया है। चंपा सिंह जब 11 साल की थीं, तभी उनके पिता का देहांत हो गया था और कम उम्र में ही शादी हो गई। कुछ समय के बाद पति का भी देहांत हो गया। ऐसे में चंपा और उनकी मां के लिए गुजर-बसर करना आसान नहीं था। लेकिन चंपा के जीवन में आजीविका मिशन सहारा बना। उन्होंने कृषि सखी का प्रशिक्षण लिया और अपनी आय बढ़ाने के साथ-साथ अब तक कई राज्यों की साढ़े पांच हजार से अधिक महिला किसानों को प्रशिक्षित भी कर चुकी हैं। आज उनकी एक दुकान है जो जैविक दुकान के नाम से मशहूर है और खेतों में जैविक खाद से उर्वरता बढ़ाने का मंत्र भी लोगों को दे रही हैं। वे कहती हैं, *"पहले साल में 40-50 हजार रुपये की भी आमदनी नहीं होती थी, लेकिन बेहतर प्रशिक्षण और अवसर के बाद अब वे ढाई-तीन लाख रुपये सालाना कमा रही हैं।"* प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद में उन्होंने बेहद उत्साह के साथ आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने का इरादा भी जाहिर किया था।

कौल कंडोली तीर्थस्थल, जिसे श्री माता वैष्णोदेवी तीर्थ का पहला पड़ाव माना जाता है। प्रतिदिन सैकड़ों स्थानीय और बाहरी

तीर्थयात्री यहां आते हैं। मंदिर में चढ़ावे के साथ फूल-माला आदि भी चढ़ता है लेकिन पूजा के बाद उसका विसर्जन चुनौती होती है। ऐसे में पूजा अवशेषों को कम करने के लिए आजीविका मिशन के तहत स्थापित संजीवनी स्व सहायता समूह के साथ काम करने वाली 10 महिलाओं के एक समूह ने अनोखा तरीका निकाला और सूखे फूलों के अवशेष को अगरबत्ती में बदलना शुरू किया। इन अगरबत्तियों को कौल कंडोली और कटरा में वैष्णोदेवी तीर्थ सहित जम्मू के अन्य प्रमुख मंदिरों में बेचा जाता है। उधमपुर की 31 वर्षीय रेखा रानी संजीवनी ग्रुप की टीम लीडर हैं। उनके समूह की अधिकांश महिलाएं ग्रामीण पृष्ठभूमि की हैं। इसलिए इन महिलाओं को आत्मनिर्भरता की भावना देने के लिए रेखा रानी ने उन सभी को उनकी समझ और विशेषज्ञता के अनुसार अलग-अलग कार्य दिए हैं यानी मंदिर से फूलों का अवशेष इकट्ठा करने, अगरबत्ती बनाने से लेकर मंदिर और अन्य क्षेत्रों में बेचने तक, सबके हिस्से का काम निर्धारित है। रेखा बताती हैं कि उनके समूह से दो-तीन महिलाएं सुबह कौल कंडोली मंदिर जाकर लगभग एक क्विंटल फूलों के रूप में पूजा अवशेष इकट्ठा करती हैं। उसके बाद महिलाओं का दूसरा समूह फूलों की पंखुड़ियों को अलग कर उन्हें धूप में सुखाने का काम करता है। फूल सूख जाने के बाद समूह की सभी महिलाएं किसी एक के आवास पर सूखे फूलों को पीसने और अगरबत्ती बनाने के लिए एकत्रित होती हैं। इसकी बिक्री स्थानीय स्तर पर और फिर वैष्णोदेवी श्राइनबोर्ड की ओर से होती है।

जिस समय पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था लोगों को बैंक सेवायें प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उसी कठिन समय में बीसी सखी (बैंक कॉरेसपोंडेंट-सखी) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों को उनके गांवों में जाकर वित्तीय सेवायें

8.62 करोड़ परिवार स्वयं सहायता समूहों से जुड़े

- **4,15,622** ग्रामीण संगठनों को बढ़ावा।
- **33,16,398** स्वयं सहायता समूहों को अब तक रिवॉल्विंग फंड जारी किया गया है।
- **4,75,215** करोड़ रुपये रिवॉल्विंग फंड की राशि अभी तक जारी की जा चुकी है।
- **23,17,553** समूहों को कम्युनिटी इंवेस्टमेंट फंड के तहत सहायता दी गई।
- **15,017.28** करोड़ रुपये अभी तक कम्युनिटी इंवेस्टमेंट फंड के तहत जारी किए गए हैं।
- **3,84,669** कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के तौर पर महिलाओं को जोड़ा।

16,89,27,854 मास्क कोविड काल में स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए।

5,29,741 रक्षक उपकरणों का निर्माण कोविड के दौरान समूहों ने किया।

5,13,059 लीटर सैनेटाइजर बनाया गया कोविड काल में।

1,22,682 सामुदायिक किचन के माध्यम से भोजन दिया गया।

(*आंकड़े 02 नवंबर 2022 तक, स्रोत: https://nrlm.gov.in/dashboardForOuter.do?methodName=dashboard)

मिशन के उद्देश्य

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

ग्रामीण विकास मंत्रालय का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्यधारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये उनकी गरीबी दूर करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने जून, 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की शुरूआत की थी। 2015 में इसका नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) किया गया। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। यह योजना स्वरोजगार को बढ़ावा देने और ग्रामीण गरीबों के संगठन पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को स्वरोजगार और कुशल मजदूरी के रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाकर गरीबी को कम करना है जिसके परिणामस्वरूप गरीबों के लिए स्थायी और विविध आजीविका विकल्प उपलब्ध हैं। यह गरीबों की आजीविका में सुधार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहल में से एक है।

ज्यादा परिवारों को लाभ

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों को लक्ष्य समूह बनाकर दायरे में रखा गया था। जब 2014-2015 में पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने योजना का आकलन किया तो उसका दायरा भी बढ़ाया और नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) किया। अब सामाजिक आर्थिक और जातिगत गनगणना 2011 के डेटाबेस के अनुसार कम से कम एक तरह के अभाव वाले सभी परिवारों को मिशन के लक्ष्य समूह में शामिल कर लिया गया। इसका असर यह हुआ कि अभावग्रस्त परिवार की महिलाएं चाहे उनके पास बीपीएल कार्ड हो या नहीं, सरकार की मशीनरी अभावग्रस्त परिवारों तक पहुंची। इससे महिला स्वयं सहायता समूहों की संख्या तेजी से बढ़ी। तब से अपने नाम और लक्ष्य को चरितार्थ कर रहा यह मिशन, राष्ट्र-समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। आर्थिक प्रगति के कारण महिलाएं और उनका परिवार घोर गरीबी से बाहर आने लगा है, उनके जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। मिशन की आधारशिला समुदाय आधारित है और ग्रामीण महिलाएं इसके मूल में हैं। मिशन ने महिला सशक्तीकरण के लिए एक बड़ा मंच प्रदान किया है।

उपलब्ध करा रही थीं। बीसी सखी भोजलता राणा, नीलम राय, समरीन खान, मालती ग्रियास, गायत्री मरावी तथा ज्योति बरकड़े ने लॉकडाउन कार्यकाल में मार्च 20 से लगातार करोड़ों के वित्तीय लेनदेन कर ग्रामीणों को गांव में ही सेवाएं प्रदान की। ये सभी बीसी दीदी, पहले समूह से जुड़कर केवल लेनदेन का काम करती थीं। तब इन्हें मासिक लगभग 1000 से 1200 रुपये मिलते थे और मुश्किल से जीवन यापन हो पाता था। इसके बाद ग्रामीण बैंक व महाराष्ट्र बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोग द्वारा अनुबंधित बीसी कॉरपोरेट के सहयोग से इन्हें उसी शाखा की निकटतम पंचायत में बीसी प्वाइंट उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही आसान किस्तों में लैपटॉप व आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये गए। आज ये बीसी सखी दीदी लगभग 6 से 7 हजार रुपये महीने का लाभ केवल बैंक कॉरेसपोंडेंट के काम से प्राप्त करती हैं। इसके अलावा इनकी कृषि, पशु पालन एवं अन्य आजीविका गतिविधियों से भी नियमित आय होती है।

लखपति महिला किसान के रूप में मिसाल बन चुकी हैं माला देवी...देवघर जिले के सारवां प्रखंड के खेरवा गांव की रहने वाली माला देवी ने समूह के माध्यम से खेती के जरिए अपनी आजीविका को सबल किया है। 2017 में खेरवा आजीविका सखी मंडल से जुड़ने के पहले माला देवी को अपने परिवार का भरण-पोषण करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। परिवार में सिर्फ उनके पति की कमाई से किसी तरह से दो वक्त की रोटी का गुजारा हो पाता था। समूह से जुड़कर उन्होंने छोटे-छोटे ऋण लेकर सब्जियों की खेती करना शुरू किया। वर्तमान में माला देवी सब्जियों की खेती से साल में एक लाख से लेकर 1.5 लाख तक की आमदनी कर लेती है। वे अपने खेत में गोभी, टमाटर,मिर्च,कद्दू, खीरा आदि की फसल लगाती है। माला देवी से प्रेरणा लेकर उनके गांव की अन्य दीदियां भी खेती की ओर अग्रसर हो रहीं हैं।

चंपा, रेखा, भोजलता, समरीन, माला जैसी प्रेरणा देने वालीं ऐसी स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की कहानियां लाखों में है, जो यह साबित करती है कि भारत की नारी शक्ति अगर कुछ करने की ठान ले तो परिवार, समाज और राष्ट्र में बदलाव लाया जा सकता है क्योंकि जब नारी सशक्त होती है तो एक व्यक्ति या परिवार नहीं, बल्कि पूरा समाज और देश सशक्त होता है।

अकसर यह देखा गया है कि जिस भी सेक्टर में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, उस क्षेत्र में, उस कार्य में सफलता निश्चित हो जाती है। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता इसका बेहतरीन उदाहरण है, जिसको महिलाओं ने नेतृत्व दिया है। आज गांवों में खेती हो, पशुपालन का काम हो, डिजिटल सेवाएं हों, शिक्षा हो, बैंकिंग सेवाएं हों, बीमा से जुड़ी सेवाएं हों, मार्केटिंग हो, भंडारण हो, पोषण हो, अधिक से अधिक क्षेत्रों में महिलाओं-लड़कियों को प्रबंधन

> महिला स्वयं सहायता समूहों की ताकत आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत अहम एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आज प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है।
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

क्या	वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2013-14 तक की प्रगति	वि.वर्ष 2014-15 से सितंबर 22 तक प्रगति	सितंबर 2022 तक की उपलब्धि
स्वयं सहायता समूहों में शामिल परिवारों की संख्या	2.36 करोड़	6.23 करोड़ के करीब	8.59 करोड़ से ज्यादा
एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूह की संख्या	21.31 लाख	57.84 लाख	79.15 लाख
2021-22 में बैंकों द्वारा वितरित ऋण की राशि	22,944.16 करोड़ रुपये	5,31,936.15 करोड़ रुपये	5,54,959.04 करोड़ रुपये
स्वयं सहायता समूहों को सहायता की राशि	1,501.58 करोड़ रुपये	17,947.63 करोड़ रुपये	19,449.21 करोड़ रुपये

31 मार्च 2014 तक स्वयं सहायता समूहों पर एनपीए 9.58% था। 2022 में यह दर घटकर 2.23% पर आ गई।

से जोड़ा जा रहा है। इसमें दीन दयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय आजीविका मिशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत समूहों से जुड़ीं महिलाएं विविध मोर्चों को संभालती हैं। इनमें कुछ महिलाएं पशु सखी के रूप में, कोई कृषि सखी के रूप में, कोई बैंक सखी के रूप में, कोई पोषण सखी के रूप में अपने काम को बेहतर दिशा दे रही हैं। महिलाओं के नेतृत्व की सफलता का एक उत्तम उदाहरण जल जीवन मिशन भी है। हर घर पाइप से जल पहुंचाने के इस अभियान में सिर्फ 3 वर्षों में 7 करोड़ से अधिक नए पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इनमें से बहुत जगहों पर नल जल परियोजनाओं का प्रबंधन भी आज इन स्वयं सहायता समूहों के हाथ में है। नल से जल योजना के लिए बनी पानी समितियों में महिलाओं की भागीदारी हो, पाइपलाइन का रखरखाव हो या पानी की जांच, समूह से जुड़ी महिलाएं अपनी भूमिका को स्वयं सहायता से अधिक राष्ट्र सहायता समूह के रूप में बेहतर ढंग से निभा रही हैं। जब कोविड जैसी वैश्विक महामारी ने दुनिया को थामने की कोशिश की, तब भी भारत की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी नारी शक्ति इस लड़ाई में देश के साथ खड़ी थीं। करीब 4 लाख सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (सीआरपी) ने 5.6 करोड़ स्वयं सहायता समूह सदस्यों को कोविड के अनुरूप व्यवहार का प्रशिक्षण प्रदान किया। जबकि 3 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्यों ने 16 करोड़ से अधिक फेस मास्क का उत्पादन किया, 5 लाख लीटर से अधिक सैनिटाइजर और 1 लाख से अधिक लीटर हैंड वाश का निर्माण किया। एक लाख से अधिक संचालित सामुदायिक रसोई के माध्यम से करोड़ों लोगों को भोजन प्रदान किया गया।

प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक पहुंच का लक्ष्य

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्ष्य 10 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को आजीविका एवं आय में सुधार के लिए सहायता प्रदान करना है। इसे देश भर के 6,861 ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है। इस मिशन की 2011 से 2014 तक की प्रगति को अगर देखें तो पांच लाख स्वयं सहायता समूह बने थे और सिर्फ 50-52 लाख परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया था। लेकिन 2014 के बाद से इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आया। पिछले 8 वर्षों में स्वयं सहायता समूहों को सशक्त

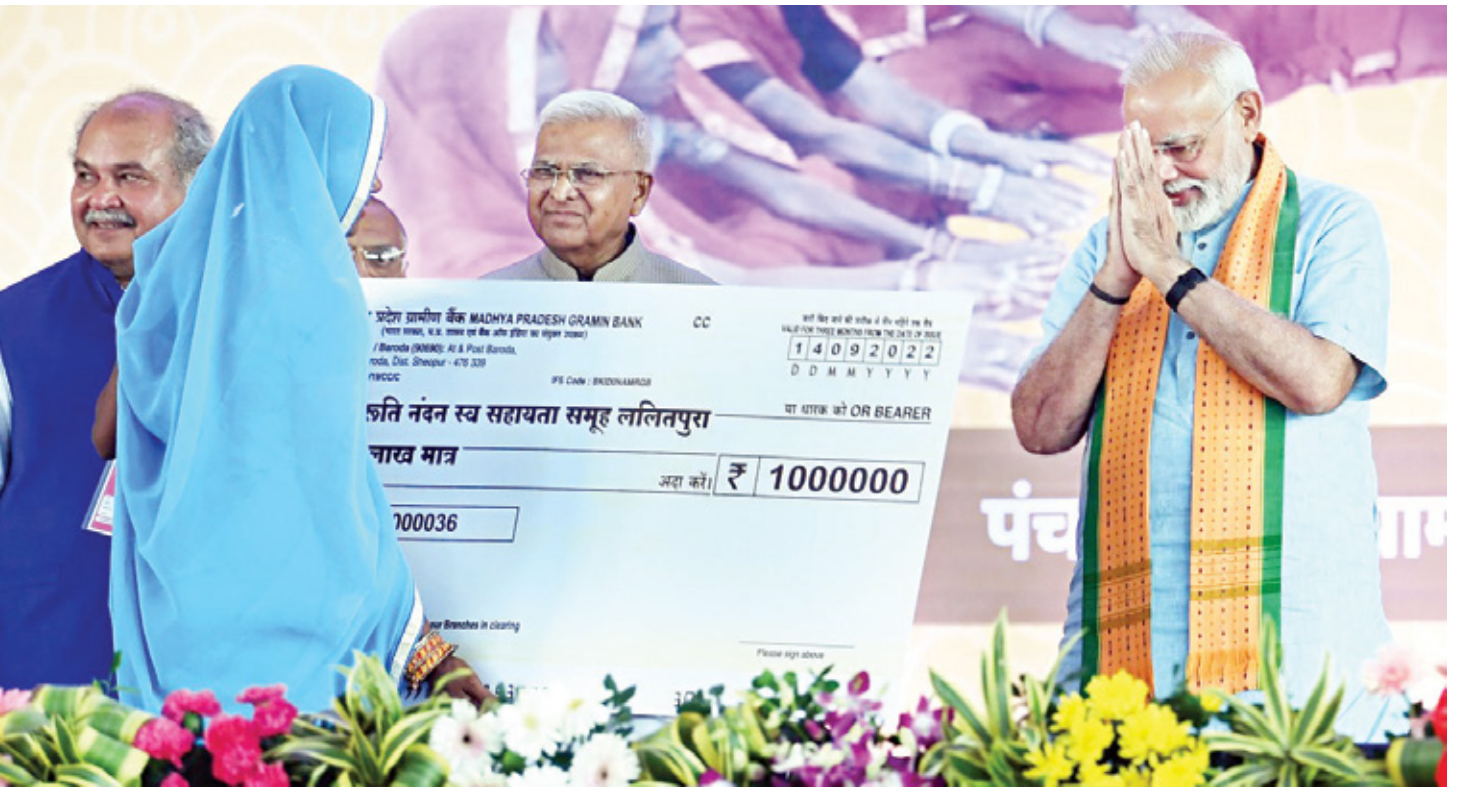

बनाने में केंद्र सरकार ने हर प्रकार से मदद की है। आज पूरे देश में 8.5 करोड़ से अधिक महिलाएं इस अभियान से जुड़ चुकी हैं। यानी एक प्रकार से साढ़े आठ करोड़ परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इस योजना के प्रति विजन और लक्ष्य है कि हर ग्रामीण परिवार से कम से कम एक महिला, एक बहन-बेटी या मां, इस अभियान से जुड़े। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में 7 से 20 सितंबर तक 15 दिवसीय देशव्यापी अभियान चलाया, ताकि दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छूटे हुए गरीब ग्रामीण और गरीब महिलाओं को महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इस दौरान आयोजित सामाजिक लामबंदी कार्यक्रम में प्रत्येक सदस्य को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वे अपने साथ एक ऐसे मित्र, पड़ोसी को साथ लाएं जो किसी भी स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं हैं। 31 अगस्त तक डीएवाई-एनआरएलएम के तहत 8.5 करोड़ से अधिक परिवारों को लगभग 80 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जोड़ा जा चुका है।

राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 2014 से पहले के 5 वर्षों में जितनी मदद दी गई, बीते 7 साल में उसमें लगभग 13 गुणा

मिशन की आधारशिला है इसका 'समुदाय संचालित' दृष्टिकोण, जिसने महिला सशक्तीकरण के लिए एक बड़ा मंच तैयार किया।

बढ़ोतरी हुई है। हर स्वयं सहायता समूह (सेल्फ हेल्प ग्रुप) को पहले जहां 10 लाख रुपये तक का बिना गारंटी का ऋण मिलता था, अब ये सीमा भी दोगुनी यानी 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई है। फूड प्रोसेसिंग से जुड़े स्वयं सहायता समूह को नई यूनिट लगाने के लिए 10 लाख रुपये से लेकर 3 करोड़ रुपये तक की मदद दी जा रही है।

महिला सशक्तीकरण की नई सोच

पिछली शताब्दी के भारत और इस शताब्दी के नए भारत में एक बहुत बड़ा अंतर हमारी नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व के रूप में आया है। आज के नए भारत में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। आजादी की लड़ाई में सशस्त्र संघर्ष से लेकर सत्याग्रह तक, देश की बेटियां किसी से पीछे नहीं रहीं हैं। आज जब भारत अपनी आजादी का अमृत

> महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण उन्हें समाज में भी उतना ही सशक्त बनाता है। हमारी सरकार ने बेटियों के लिए सारे, जितने दरवाजे बंद थे ना, सारे दरवाजे खोल दिए हैं। – नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

महोत्सव मना रहा है, तब राष्ट्र ने देखा है कि कैसे जब हर घर में तिरंगा फहराया गया तो उसमें महिला स्वयं सहायता समूहों ने बड़ा काम किया है। उनके बनाए तिरंगों ने राष्ट्रीय गौरव के इस क्षण को चार चांद लगा दिए। कोविड काल की संकट की घड़ी में जब लोग अपने घरों में बंद थे और खुद को सुरक्षित रखने के प्रयासों में जुटे थे, तब भी मानव मात्र की सेवा करने के इरादे से महिला स्वयं सहायता समूहों ने बहुत बड़ी मात्रा में मास्क बनाए, पीपीई किट बनाने से लेकर लाखों-लाख तिरंगे बनाए... यानी एक के बाद एक हर काम में देश की नारी शक्ति ने हर चुनौती को अपनी उद्यमिता से सिद्ध कर देश में नया विश्वास पैदा किया।

जब एक समूह का जन्म होता है तो 10-12 महिलाएं इकट्ठी होती है, एक-एक कदम फूंक-फूंक कर बढ़ाती हैं, कुछ पैसे इधर-उधर से इकट्ठे करके कोशिश होती है, तो वह स्वयं सहायता समूह का रूप लेता है। लेकिन राष्ट्र पर आई कोविड जैसी वैश्विक आपदा हो या फिर तिरंगा फहराने का उत्सव या फिर सरकारी योजनाओं में भागीदारी के साथ-साथ उसकी निगरानी, अपने सामर्थ्य और संकल्प के कारण ये स्वयं सहायता समूह सही मायने में राष्ट्र सहायता समूह बन जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, "कल जो स्वयं सहायता समूह थे, आज राष्ट्र सहायता समूह बनकर राष्ट्र की सहायता कर रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों की यही ताकत आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आज प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है।"

स्वयं सहायता समूहः सेवा-सफलता की मिसाल

स्वयं सहायता समूह की वजह से जो परिवर्तन प्रत्येक क्षेत्र में आ रहा है, उससे एक बेहतर समाज और सशक्त राष्ट्र बनाने में देश सफल होगा। कोविड काल में जिस प्रकार से स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला समूह ने देशवासियों की सेवा की वह अभूतपूर्व है। अपने परिवार को बेहतर जीवन देने के साथ-साथ, देश के विकास को आगे बढ़ाने में जुटी करोड़ों महिलाएं आज स्वयं के साथ-साथ राष्ट्र के विकास की वाहक बन गई हैं। स्वयं सहायता समूह और दीन दयाल अंत्योदय योजना, आज ग्रामीण भारत में

एक नई क्रांति ला रही है और यह संभव हुआ है स्वयं सहायता समूहों की वजह से। पिछले 6-7 सालों के दौरान स्वयं सहायता समूहों में 3 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। यह इसलिए अहम है क्योंकि अनेक वर्षों तक महिलाओं की आर्थिक सशक्तीकरण की उतनी कोशिश ही नहीं की गई थी, जितनी होनी चाहिए थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब देश की करोड़ों महिलाएं ऐसी थीं जिनके पास बैंक खाता तक नहीं था, वो बैंकिंग सिस्टम से कोसों दूर थीं। इसलिए ही सबसे पहले जन धन खाते खोलने का बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। फिर न केवल बैंक खाते खोले, बल्कि बैंकों से ऋण लेना भी आसान कर दिया।

देश में उद्यमियों द्वारा बैंक से मिले ऋण को वापस न करने की कई खबरें आती रहती थी, लेकिन इन महिलाओं ने न केवल ऋण लिया, बल्कि उसकी वापसी को लेकर भी अच्छा काम किया है। जहां पहले 9 प्रतिशत बैंक ऋण फंसे रह जाते थे, अब यह दर घटकर दो-ढाई प्रतिशत तक आ गई है। एक जिला-एक उत्पाद के माध्यम से हर जिले के लोकल उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने का अभियान चल रहा है, जिसका बहुत बड़ा लाभ महिला स्वयं सहायता समूहों को भी हो रहा है। ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते प्रचलन का लाभ केंद्र सरकार के GeM यानी गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पोर्टल के जरिए स्वयं सहायता समूहों तक पहुंचाने और उनके उत्पादों की बिक्री के लिए पोर्टल में 'सरस' नाम से एक विशेष स्थान रखा गया है। इसके माध्यम से वे अपने उत्पाद सीधे सरकारी विभागों को बेच सकते हैं।

जीवन भी हो रहा सुगम

2014 के बाद से ही देश, महिलाओं की गरिमा बढ़ाने, महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान में जुटा हुआ है। शौचालय के अभाव में जो दिक्कतें आती थी, रसोई में लकड़ी के धुएं से जो तकलीफ होती थी, पानी लेने के लिए दो-दो, चार-चार किलोमीटर जाना पड़ता था। देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर, 9 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन देकर और

आज पूरे देश में 8.5 करोड़ से अधिक महिलाएं इस अभियान से जुड़ चुकी हैं।

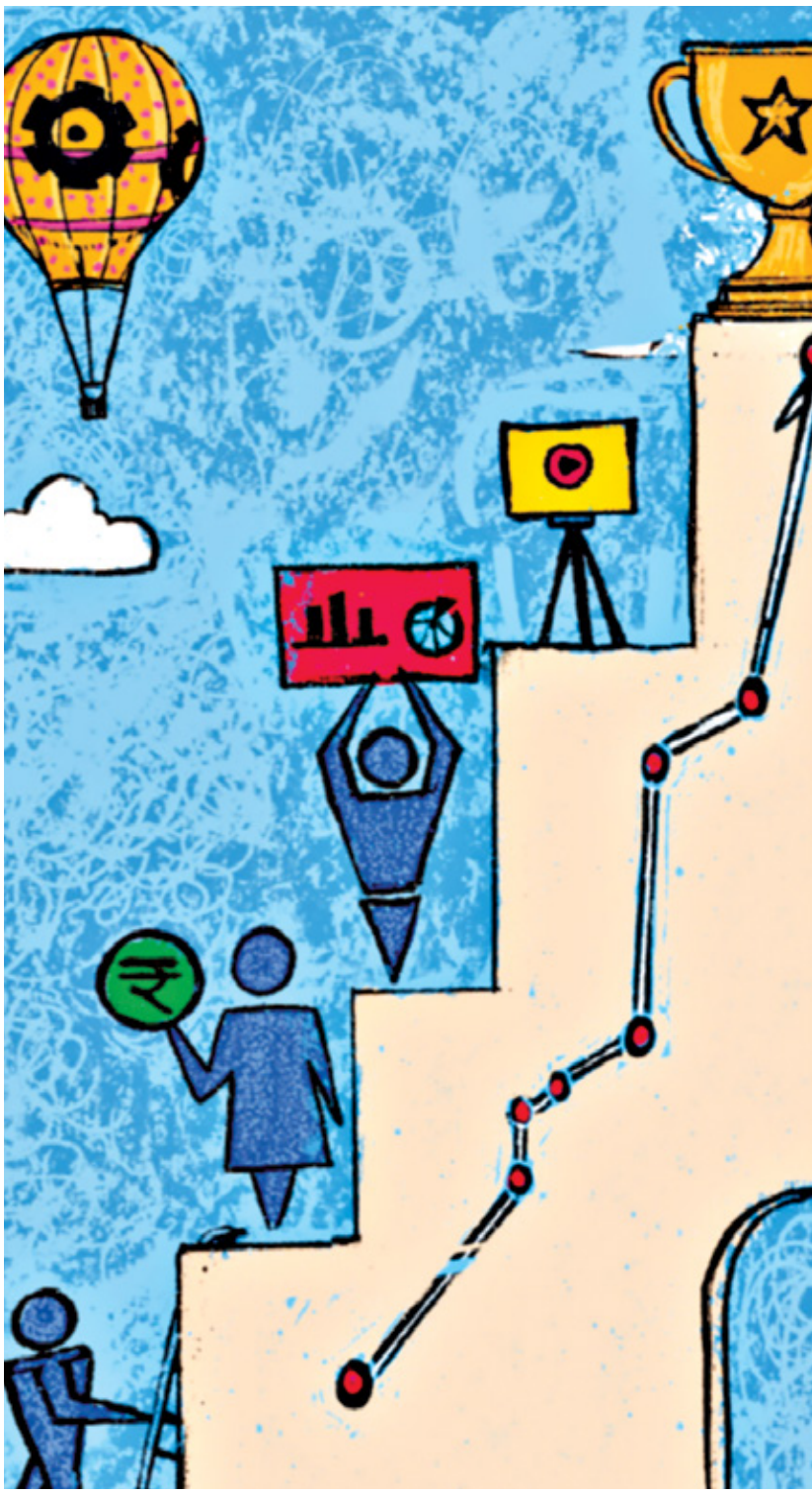

> आज पूरे देश में 8 करोड़ से अधिक बहनें इस अभियान से जुड़ चुकी हैं। मतलब 8 करोड़ परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर ग्रामीण परिवार से कम से कम एक महिला, एक बहन हो, बेटी हो, मां हो इस अभियान से जुड़े। **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।

करोड़ों परिवारों को नल से जल देकर जीवन आसान बनाया है। गर्भावस्था के दौरान सहायता देने के लिए मातृ वंदना योजना शुरु की गई। इसके तहत 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक सीधे गर्भवती महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। आयुष्मान भारत योजना के तहत मिल रहे 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज ने भी गरीब परिवार की बहनों की बहुत बड़ी मदद की है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के अच्छे परिणाम आज देश अनुभव कर रहा है। बेटियां ठीक से पढ़ाई कर सकें, उनको स्कूल बीच में छोड़ना ना पड़े, इसके लिए स्कूलों में बेटियों के लिए अलग से शौचालय बनाए, सेनिटेरी पैड्स की व्यवस्था की गई। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लगभग ढाई करोड़ बच्चियों के अकाउंट खोले गए हैं।

आज जन धन बैंक खाते देश में महिला सशक्तीकरण के बहुत बड़े माध्यम बने हैं। महिलाओं को संपत्ति में मालिकाना हक दिया जा रहा है। जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश की 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को सीधा उनके नाम पर घर देकर मालकिन बनाया है। मुद्रा योजना के तहत भी अभी तक देशभर में 19 लाख करोड़ रुपये का बिना गारंटी का ऋण छोटे-छोटे व्यापार-कारोबार के लिए दिया जा चुका है। उसमें से लगभग 70 प्रतिशत महिलाएं हैं जो उद्यम करती हैं। केंद्र सरकार के ऐसे प्रयासों के कारण आज घर के आर्थिक फैसलों में महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है।

स्वयं सहायता समूह और भविष्य की संभवानाएं

आजादी के 75 वर्ष का ये समय नए लक्ष्य तय करने और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का है। महिलाओं की समूह शक्ति को भी अब नई ताकत के साथ आगे बढाना है। सरकार लगातार वह माहौल, वह स्थितियां बना रही है, जहां से महिलाएं गांवों को समृद्धि और संपन्नता से जोड़ सकती हैं। कृषि और कृषि

आधारित उद्योग जैसे क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूह के लिए अनंत संभावनाएं हैं। गांवों में भंडारण और कोल्डचेन की सुविधा शुरू करनी हो, खेती की मशीनें लगानी हों, दूध-फल-सब्जी को बर्बाद होने से रोकने के लिए कोई प्लांट लगाना हो, ऐसे अनेक काम के लिए विशेष फंड बनाया गया है। इस फंड से मदद लेकर स्वयं सहायता समूह भी ये सुविधाएं तैयार कर सकते हैं।

केंद्र सरकार, महिला किसानों के विशेष प्रशिक्षण और जागरूकता को भी निरंतर बढ़ावा दे रही है। इससे अभी तक लगभग सवा करोड़ किसान और पशुपालक महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। भारत में बने खिलौनों को भी सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है, इसके लिए हर संभव मदद भी दे रही है। विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों की महिलाएं तो पारंपरिक रूप से इससे जुड़ी हैं। इसमें भी स्वयं सहायता समूह के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इसी प्रकार, आज देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का अभियान चल रहा है। इसमें स्वयं सहायता समूह की दोहरी भूमिका है। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जागरूकता भी बढ़ानी है और इसके विकल्प के लिए भी काम करना है। प्लास्टिक के थैले की जगह, जूट या दूसरे आकर्षक बैग ज्यादा से ज्यादा बना रही हैं।

निश्चित तौर से स्वयं सहायता समूह गरीबों और महिलाओं की उन्नति के साथ-साथ राष्ट्र की प्रगति का भी आधार बन चुके हैं। महिला शक्ति को अवसर मिला तो आत्मविश्वास जगा और समूह की शक्ति का अहसास हुआ। इससे स्वावलंबन की राह पर आगे बढ़ीं महिलाओं को कहीं बैंक सखी तो कहीं पशु सखी, कहीं कृषि सखी नाम मिला। स्टार्ट अप ग्राम उद्यमिता में भी महिलाएं आज आगे बढ़ रही हैं और उनके सपने अब सिर्फ सपने नहीं रहे, बल्कि साकार हो रहे हैं। सही मायने में नए भारत के केंद्र में शामिल नारी शक्ति विकास के खुले गगन में उन्मुक्त उड़ान भर रही हैं। इसलिए कहते हैं- "मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नही होता हौसलों से उड़ान होती है।" ●

डिफेंस एक्सपो-मिशन लाइफ जैसी वैश्विक पहल के साथ गुजरात को विकास की सौगात

प्रगति भी प्रकृति भी

गुजरात देश के उन राज्यों में शामिल है, जहां हाल के समय में कई ऐसी शुरुआत हुई हैं, जिन्होंने न केवल इस राज्य का मान देश में बढ़ाया है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की प्राण प्रतिष्ठा में भी अपना योगदान दिया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लेकर ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन और पहले स्मार्ट फिनटेक शहर गिफ्ट सिटी और भारत के पहले बुलियन एक्सचेंज से लेकर देश के पहले सोलर गांव मोढेरा तक गुजरात की विकास यात्रा में ऐसे कई पड़ाव आए हैं। अबकी बार गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो और केवड़िया में मिशन लाइफ का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा में दो और पहलों को जोड़ा...

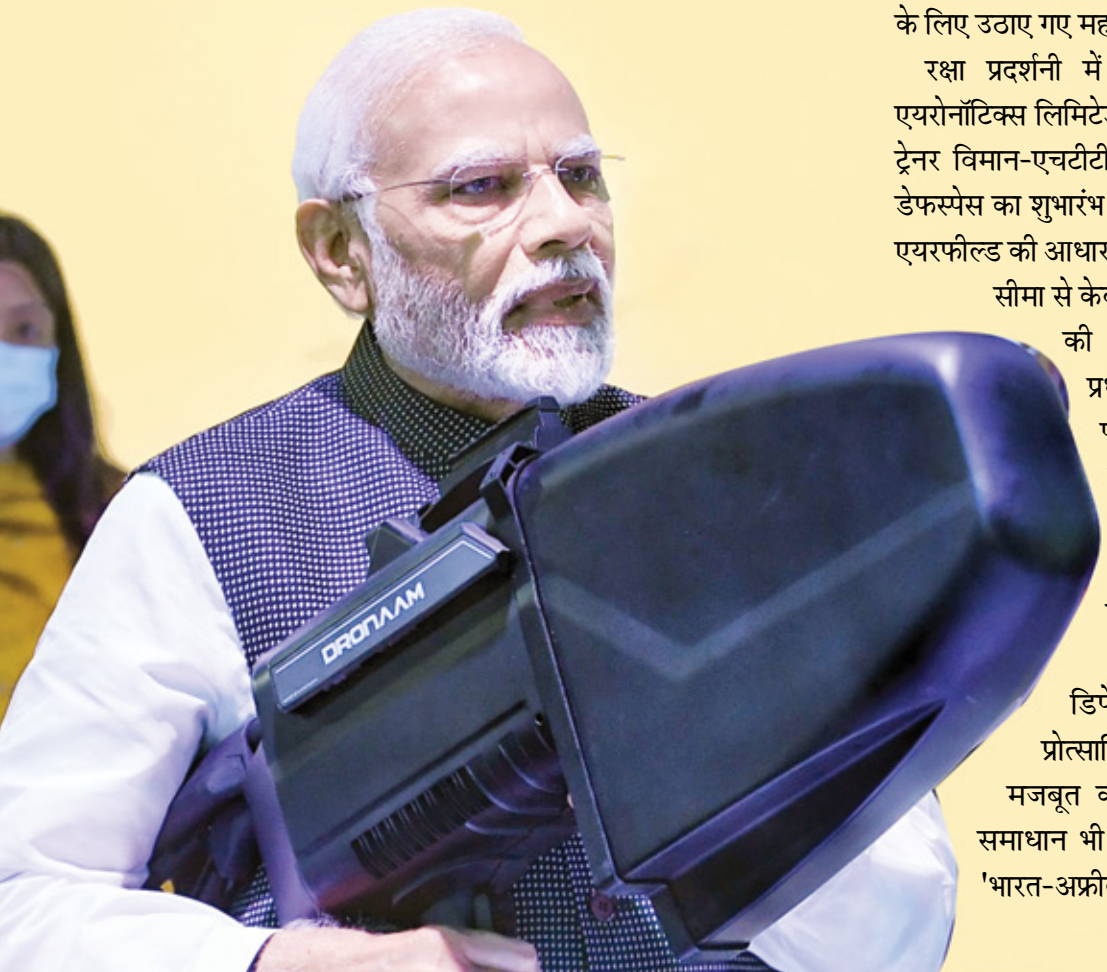

गुजरात का गांधी नगर अमृतकाल में विकास की यात्रा में एक नया पड़ाव लेकर आया। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत के लिए देश में पहली बार आयोजित पूर्णतः स्वदेशी रक्षा प्रदर्शनी 2022 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर को शुभारंभ किया, जिसका विषय 'पाथ टू प्राइड-गौरव की राह' था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा, "यह नए भारत और इसकी क्षमताओं की एक तस्वीर पेश करता है जिसका संकल्प हमने अमृतकाल में लिया है। इसमें युवाओं की शक्ति, सपने, संकल्प, साहस और युवा का सामर्थ्य है। दुनिया के लिए आशाएं और मित्र देशों के लिए अवसर है।"

रक्षा प्रदर्शनी 2022 में भारत के रक्षा उद्योग, भारतीय रक्षा उद्योग से जुड़े संयुक्त उद्यम, एमएसएमई और स्टार्टअप सहित 1300 से अधिक प्रदर्शक शामिल हुए। यहां 451 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रदर्शनी की शुरुआत से पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "यह रक्षा प्रदर्शनी मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक है।"

रक्षा प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन किए गए स्वदेशी ट्रेनर विमान-एचटीटी-40 का अनावरण और मिशन डेफस्पेस का शुभारंभ किया। साथ ही, गुजरात में डीसा एयरफील्ड की आधारशिला भी रखी। डीसा अंतरराष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किमी दूर है। एयरफील्ड की जरूरत और महत्व को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा, "अगर हमारी फोर्सेस विशेषकर हमारी वायु सेना डीसा में होगी तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का और बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'मिशन डिफेंस स्पेस' न केवल नवाचार को प्रोत्साहित करेगा और हमारे बलों को मजबूत करेगा बल्कि नए और अभिनव समाधान भी प्रदान करेगा।' रक्षा प्रदर्शनी में 'भारत-अफ्रीका : रक्षा और सुरक्षा सहयोग में

यूं समझें रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ताकत

- पिछले 5 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात 8 गुना बढ़ा है। हम दुनिया के 75 से अधिक देशों में रक्षा सामग्री और उपकरणों का निर्यात कर रहे हैं।
- 2021-22 में रक्षा निर्यात 1.59 अरब डॉलर यानी करीब 13 हजार करोड़ रु.तक पहुंचा। 40 हजार करोड़ रु. तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
- रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उपकरणों की चौथी सूची भी जारी की गई जिन्हें केवल देश के भीतर ही खरीदा जाएगा। इस सूची में 101 रक्षा मद शामिल किए जाने के बाद अब कुल 411 ऐसे रक्षा क्षेत्र के उपकरण हो गए जो सिर्फ 'मेक इन इंडिया' के तहत खरीदे जाएंगे।

आठ साल पहले तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा आयातक देश माना जाता था लेकिन मेक इन इंडिया आज रक्षा क्षेत्र की सक्सेस स्टोरी बन रहा है। विश्व स्तर पर रक्षा क्षेत्र में कुछ निर्माण कंपनियों ने एकाधिकार बना रखा था लेकिन भारत के युवाओं ने रक्षा उद्योग में इस एकाधिकार को तोड़ने की ताकत दिखाई है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री।

तालमेल के लिए रणनीति अपनाने' विषय पर दूसरी भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता भी हुई। दूसरा हिंद महासागर क्षेत्र+ (आईओआर+) सम्मेलन भी आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, 'दुनिया की भारत से उम्मीदें बढ़ी हैं, भारत उन्हें पूरा करेगा। इसलिए यह डिफेंस एक्सपो भारत के प्रति वैश्विक भरोसे का भी प्रतीक है।'

गुजरात दौरे पर 15,670 करोड़ रुपये की सौगातें

"विकसित राष्ट्र के लिए विकसित गुजरात" का मंत्र साथ लेकर चलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19-20 अक्टूबर को दो दिवसीय गुजरात दौरे पर रहे। दौरे में राजकोट, व्यारा तापी, जूनागढ़, त्रिमंदिर-अडालज में 15,670 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा, "जब गरीब सशक्त होते हैं, तो वे गरीबी से तेजी से बाहर निकलने लगते हैं।"

राजकोट को मिलीं 5860 करोड़ रुपये की परियोजनाएं

गुजरात के राजकोट में करीब 5860 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई और राष्ट्र को समर्पित की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने लाइट हाउस परियोजना में बने 1144 घर समर्पित किए तो इंडिया अर्बन हाउसिंग कांक्लेव का उद्घाटन भी किया। जल आपूर्ति परियोजना ब्राह्मणी-2 बांध से नर्मदा नहर पंपिंग स्टेशन तक मोरबी-बल्क पाइपलाइन समर्पित की और राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के राजकोट-गोंडल-जेतपुर खंड के मौजूदा फोर-लेन को छह लेन बनाने सहित कई अन्य परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी।

सरदार पटेल की धरती से मिशन लाइफ का संदेश

हम अपनी जीवन-शैली के लिए पृथ्वी की तुलना में 1.6 गुना अधिक संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बड़ी ज्यादती से ही बड़ी असमानता हो रही है। मैं पर्यावरण की दृष्टि से अच्छी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता और अक्षय ऊर्जा में निवेश बढ़ाने के संकल्प से बहुत उत्साहित हूं।
-एंटोनियो गुटेरेस, संयुक्त राष्ट्र महासचिव।

LiFE, 'लाइफ स्टाइल ऑफ द प्लानेट, फॉर द प्लेनेट एंड बाय द प्लानेट' के मूल सिद्धांत पर चलता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो। जीवनशैली में बदलाव से पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है।
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री।

LiFE के अंतर्गत भारत ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए 75 ईको-फ्रेंडली कार्यों की सूची जारी कर इन्हें मानने की अपेक्षा की है।

भारत वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड के वैश्विक अभियान की अगुवाई कर रहा है। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गठबंधन के निर्माण का नेतृत्व करके, भारत ने दुनिया को पर्यावरण संरक्षण की अपनी अवधारणा से अवगत कराया है। अब ऐसे लक्ष्यों के प्रति अपने संकल्प को और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए दुनिया के साथ अपनी साझेदारी को और भी बढ़ाना चाहता है। इसी श्रृंखला के अगले चरण के तौर पर 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में केवड़िया के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में मिशन लाइफ (LiFE) का शुभारंभ किया।

गुजरात भारत के उन राज्यों में से एक है जिसने सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। चाहे बात नहरों पर सोलर पैनल लगाने की हो या सूखाग्रस्त इलाकों में जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए जल संरक्षण का अभियान हो गुजरात हमेशा ट्रेंडसेटर रहा है। ऐसे में गुजरात से मिशन लाइफ पी-3 मॉडल की अवधारणा को मजबूत करेगा। पी-3 यानी प्रो प्लानेट पीपल। अतीत की गलतियों से सीख लेकर ही भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, "मिशन लाइफ का मंत्र 'पर्यावरण के लिए जीवन-शैली' है।" मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को लोकतांत्रिक बनाता है जिसमें हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से योगदान दे सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अथर्ववेद के हवाले से कहा, "माता भूमिः पुत्रोहं पृथिव्याः' यानी पृथ्वी हमारी मां है और हम उसकी संतान हैं।" 'रिड्यूस, रियूज एंड रिसाइकल' और सर्कुलर इकोनॉमी भारतीय जीवन-शैली का हिस्सा रही है। मिशन लाइफ में प्रकृति के संरक्षण से जुड़ी हर उस जीवन-शैली को शामिल किया जाएगा, जिसे हमारे पूर्वजों ने अपनाया था और जिसे आज हमारी जीवनशैली का हिस्सा बनाया जा सकता है।

पर्यावरण हितैषी: अक्षय ऊर्जा में 290% की वृद्धि

- भारत में सालाना प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट करीब करीब डेढ़ टन ही है, जबकि दुनिया का औसत 4 टन प्रति वर्ष का है। भारत के पास दुनिया में अक्षय ऊर्जा की चौथी सबसे बड़ी क्षमता है।
- भारत पवन ऊर्जा में चौथे और सौर ऊर्जा में पांचवें स्थान पर हैं। पिछले 7-8 वर्षों में अक्षय ऊर्जा क्षमता में लगभग 290 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- समय-सीमा से 9 साल पहले गैर-जीवाश्म-ईंधन स्रोतों से बिजली क्षमता का 40% का लक्ष्य पा लिया है।
- निर्धारित लक्ष्य से 5 माह पहले पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल।
- राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से भारत पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत की ओर बढ़ा है।

इन पांच कदमों से दे सकते हैं LiFE को मजबूती

1. मौसम में लगे और आसपास उगे, वही खाओ-पीओ, सेहत चौकस और साथ में ईंधन और पैसे की बचत भी।
2. कदम उठाओ- नंबर 11 यानी मेरे पैर, बने रोज की सवारी। साइकिल का इस्तेमाल भी करें।
3. सही चुनें- पर्यावरण हितैषी चीजें चुनें। उदाहरण के तौर पर, सोसायटी में घर खरीद रहे हैं तो वॉटर हार्वेस्टिंग और सोलर पैनल अब देखें।
4. स्विच ऑफ करो- बिजली, पानी, गैस हो या मोटर वाहन का स्विच, जरूरत नहीं होने पर उसे ऑफ करें।
5. सबको बताओ- सबको बताकर इस आंदोलन को घर-घर ले जाओ। देश का वादा पूरा करने के लिए एक साथ काम करें।

मिशन LiFE की तीन स्तरीय रणनीति

1. व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन (मांग) में सरल लेकिन प्रभावी पर्यावरण के अनुकूल कार्यों का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना।
2. बदलती मांगों और परिस्थितियों के अनुकूल उद्योगों और बाजारों को सक्षम बनाना।
3. सतत खपत और उत्पादन के लिए प्रभावकारी नीति बनाना।

तटीय मिसिंग लिंक को मिलेगी मजबूती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जूनागढ़ में 19 अक्टूबर को 3580 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। यहां कार्गो की सुविधा होगी, फल, सब्जियां, मछली और अन्य उत्पाद भेजना आसान हो जाएगा।

मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का किया शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के त्रिमंदिर, अडालज में उत्कृष्ट मिशन स्कूलों (मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस) का शुभारंभ किया। मिशन पर कुल 10,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस मिशन में 50 हजार नए क्लासरूम और एक लाख से अधिक स्मार्ट क्लासरूम बनेंगे। यहां प्रधानमंत्री ने लगभग 4260 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया।

व्यारा, तापी में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सापुतारा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक संपर्क सड़क निर्माण, तापी और नर्मदा जिले की जलापूर्ति परियोजना सहित आसपास के जनजातीय क्षेत्र के विकास से जुड़ी 1970 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बताया कि मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत जनजातीय क्षेत्रों में लगभग 4,000 स्कूलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। ●

देश में पहली बार निजी क्षेत्र की कंपनी बनाएगी परिवहन विमान

मेक इन इंडिया
मेक फॉर द ग्लोब की दिशा में मील का पत्थर

वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की शुरुआत की, तब इस मुहिम पर कई सवाल उठाए गए। अर्थव्यवस्था को लेकर तब तक एक धारणा बन चुकी थी, कि भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेहतर नहीं कर सकता, उसे केवल सर्विस सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मेक इन इंडिया की मुहिम के साथ आज भारत मेक फॉर द ग्लोब की राह पर आगे बढ़ते हुए अपना फाइटर प्लेन बना रहा है, टैंक और सबमरीन बना रहा है। इतना ही नहीं, वैक्सीन, गैजेट, कार और मोबाइल जैसे सेक्टर में तेजी के साथ हमने कदम बढ़ाए हैं। अब बारी है उन चीजों की, जिनके निर्माण क्षेत्र पर इससे पहले कभी ध्यान नहीं दिया गया। जैसे-सेमीकंडक्टर, ड्रोन और सैन्य परिवहन विमान। इसी कमी को पूरा करने के लिए सितंबर में जहां गुजरात में देश के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला रखी गई तो 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में सैन्य परिवहन विमान के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की रखी आधारशिला...

आज भारत में, दुनिया का तेजी से विकसित होता एविएशन सेक्टर है। एयर ट्रैफिक के मामले में हम दुनिया के टॉप तीन देशों में पहुंचने वाले हैं। अगले 4-5 वर्षों में करोड़ों नए लोग हवाई सफर के यात्री होने वाले हैं। उड़ान योजना ने एविएशन सेक्टर को नई ऊंचाई दी है। ऐसे में अनुमान है कि आने वाले 10-15 वर्षों में भारत को करीब-करीब 2000 से ज्यादा पैसेंजर और कार्गो एयरक्राफ्ट की जरूरत होगी। इस बड़ी डिमांड को पूरा करने के लिए भारत अभी से तैयारी कर रहा है। इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर को गुजरात के वडोदरा में सी-295 परिवहन विमान के निर्माण के लिए प्लांट का शिलान्यास किया। यह विमान निर्माण संयंत्र देश में निजी क्षेत्र में पहला विमान निर्माण संयंत्र होगा। इस संयंत्र का उपयोग टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, स्पेन के बीच सहयोग के माध्यम से भारतीय वायु सेना के लिए 40 सी-295 विमानों के निर्माण के लिए किया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 8 वर्ष में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया तो साथ ही, आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ते हुए कई अहम पड़ावों पर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा, "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जितना जोर आज भारत का है, उतना पहले कभी नहीं था। कॉरपोरेट टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाना हो, उसे

इधर रोजगार मेले में बोले प्रधानमंत्री

देश-विदेश से उद्योग आएंगे तो स्वरोजगार के साथ रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे

धनतेरस के दिन दिल्ली में 10 लाख रोजगार के नए अवसरों के साथ हुई शुरुआत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 29 अक्टूबर को गुजरात रोजगार मेले का उद्घाटन वीडियो संदेश के माध्यम से किया। गुजरात सेवा की पंचायत पसंदगी बोर्ड में 5000 से ज्यादा लोगों को और लोक रक्षक की भर्ती में 8000 से भी ज्यादा उम्मीदवारों को मिलने वाले नियुक्ति पत्र पर खुशी जाहिए करते हुए उन्होंने कहा, "आने वाले महीनों में इस प्रकार के रोजगार मेलों का आयोजन राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर होता रहेगा। जहां केंद्र सरकार एक साल में 10 लाख नौकरियां देने पर काम कर रही है, वहीं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी इस अभियान से जुड़ रहे हैं, इससे रोजगार की संख्या में काफी वृद्धि होगी। यह अंतिम छोर तक वितरण और सरकारी योजनाओं के कवरेज की व्यापकता जैसे अभियानों को बेहद मजबूत बनाएगा। केंद्र और राज्य सरकार मिल कर ऐसी पीढ़ी को आज शासन में जोड़ रही हैं, जिसके कारण भारत सरकार का जो लक्ष्य है वह शत प्रतिशत पूर्णता, लास्ट माइल डिलीवरी में मदद करने का है। यह जो नया वर्क फोर्स यानी जो नव युवा, बेटे-बेटियां उत्साह उमंग से आएंगे, इनके आने से इस कार्य को बहुत गति मिल जाएगी।"

2021 में एयरबस के साथ हुई थी डील

सितंबर 2021 में भारत ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस (**ADSpace**) के साथ लगभग 21,000 करोड़ रुपये की डील की थी। इसमें पुराने एवरो-748 की जगह **C**-295 एयरक्राफ्ट खरीदने की डील हुई थी। 56 विमानों की मांग की गई थी। इनमें से 16 स्पेन से बनकर आएंगे और बाकी 40 गुजरात के वडोदरा में बनाए जाएंगे। यह पूरी तरह से स्वदेशी होंगे। सितंबर 2023 से अगस्त 2025 के बीच 16 एयरक्राफ्ट सौंप दिए जाएंगे। देश में बने विमानों की आपूर्ति 2026 से 2031 तक की जाएगी।

स्वदेशी कंपनियों को मिलेगा बढ़ावा

इसके लिए देश के 7 राज्यों की 25 कंपनियां 13 हजार 400 पार्ट्स और 4600 सब-असेंबली कंपोनेंट सप्लाई करेंगी। इसके अलावा इन सभी 56 विमानों को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से लैस किया जाएगा। इस लिहाज से यह परियोजना भारत में प्राइवेट सेक्टर के लिए एक अनूठा अवसर साबित होगी।

वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना हो, अनेक सेक्टर्स में 100 फीसदी विदेशी निवेश का रास्ता खोलना हो, डिफेंस, माइनिंग, स्पेस जैसे सेक्टर्स को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलना हो, श्रम कानूनों में सुधार करना हो, 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को सिर्फ 4 कोड में बदलना हो, 33 हजार से ज्यादा अनुपालनों को खत्म करना हो, दर्जनों टैक्स के जाल को खत्म करके, एक जीएसटी बनाना हो, भारत में आज इकॉनमिक रिफॉर्म की नई गाथा लिखी जा रही है।" भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए बदलावों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हमारी सरकार की निवेश के अनुकूल नीतियों का फल एफडीआई में भी दिखता है। पिछले 8 वर्षों में 160 से ज्यादा देशों की कंपनियों ने भारत में निवेश किया है। ऐसा भी नहीं कि ये विदेशी निवेश सिर्फ कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में ही आया हो। इसका फैलाव अर्थव्यवस्था के 60 से ज्यादा सेक्टर को कवर करता है, 31 राज्यों के अंदर इन्वेस्टमेंट पहुंचा है। अकेले एयरोस्पेस सेक्टर में ही 3 अरब डॉलर से अधिक का निवेश हुआ है। साल 2000 से 2014 तक (14 साल में) इस सेक्टर में जितना निवेश हुआ था, उसकी तुलना में इन 8 वर्षों में 5 गुना ज्यादा निवेश हुआ है। आने वाले वर्षों में, आत्मनिर्भर भारत अभियान के बड़े पिलर- डिफेंस और एयरोस्पेस सेक्टर होने वाले हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का स्केल 25 अरब डॉलर पार कर जाएगा। हमारा रक्षा उत्पादों का निर्यात भी 5 अरब डॉलर से अधिक होगा। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में विकसित हो रहे डिफेंस कॉरिडोर से भी इस सेक्टर को स्केल-अप करने में मदद मिलेगी।"

चुनिंदा देशों में शामिल होगा भारत

इस प्लांट के शुरू होने के साथ ही भारत एयरक्राफ्ट बनाने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। इस लिस्ट में फिलहाल अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, इटली, स्पेन, यूक्रेन, ब्राजील, चीन और जापान शामिल हैं। ●

राष्ट्रीय एकता दिवस

एक भारत, श्रेष्ठ भारत की ओर बढ़ते कदम...

भारत के लिए एकता सदा-सर्वदा विशेषता रही है। एकता की भावना भारतीय मानस के अंतर्मन में रची बसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित होकर 2014 में नूतन भारत के आधुनिक शिल्पकार व एकता के सूत्रधार, भारत रत्न, लौहपुरुष 'सरदार वल्लभ भाई पटेल' की जयंती यानि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया जिसका उद्देश्य राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने और मजबूत बनाने के लिए समर्पण की भावना को सुदृढ़ करना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में लिया हिस्सा...

लौहपुरुष 'सरदार वल्लभ भाई पटेल' की जयंती और 'राष्ट्रीय एकता दिवस' केवल तारीख भर नहीं हैं बल्कि यह भारत के सांस्कृतिक सामर्थ्य का एक महापर्व भी है। भारत के लिए एकता कभी भी विवशता नहीं रही है। भारत के लिए एकता सदा-सर्वदा विशेषता रही है। एकता हमारी विशिष्टता रही है। एकता की भावना हमारे अन्तर्मन में कितनी रची बसी है, हमें अपनी इस खूबी का अक्सर अहसास तब होता है जब भी देश पर कोई आपदा आती है और पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है। गुजरात के केवडिया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड 2022 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "ये एकजुटता, ये अनुशासन, परिवार से लेकर देश तक हर स्तर पर आवश्यक है और इसके दर्शन आज हम देश के कोने-कोने में कर भी रहे हैं। आज देश में 75000 एकता दौड़ हो रही है। देश का जन-जन सरदार पटेल की संकल्प शक्ति से प्रेरणा ले रहा है। आज देश का जन-जन अमृतकाल के 'पंच प्राणों' को जागृत करने के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए संकल्प ले रहा है।" हमारे जश्न के सांस्कृतिक तौर-तरीके अलग-अलग होते हैं, लेकिन भावना एक जैसी ही होती है। देश की ये एकता, ये एकजुटता, एक-दूसरे के लिए ये अपनापन, ये बताता है कि एक राष्ट्र के रूप में भारत की जड़ें कितनी गहरी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर, मैं सरदार साहब द्वारा हमें सौपे गए दायित्व को फिर दोहराना चाहता हूं। उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी थी कि हम देश की एकता

सरदार को श्रद्धांजलि... केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि

- स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लिया। इस दौरान राष्ट्रीय एकता दिवस परेड भी हुई जिसमें बीएसएफ और पांच राज्यों के पुलिस बल - उत्तरी क्षेत्र (हरियाणा), पश्चिमी क्षेत्र (मध्य प्रदेश), दक्षिण क्षेत्री (तेलंगाना), पूर्वी क्षेत्र (ओडिशा) और पूर्वोत्तर क्षेत्र (त्रिपुरा) से एक-एक दल शामिल हुआ। इन टुकड़ियों के अलावा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के छह पुलिस खेल पदक विजेता ने भी परेड में भाग लिया।

- आरंभ 4.0 के समापन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 97वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। केवड़िया में दो नए पर्यटक स्थलों मेज गार्डन और मियावाकी वन को समर्पित किया। मेज गार्डन 3 एकड़ में फैला हुआ है जो इसे देश का सबसे बड़ा मेज गार्डन बनाता है। यहां करीब 2.1 किमी का रास्ता है। इसे एक 'श्रीयंत्र' के आकार में डिजायन किया गया है। गार्डन में करीब 1.8 लाख पौधे लगाए गए हैं।

- मियावाकी वन करीब 2 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है। इसमें देसी फूलों का बागीचा, टिंबर गार्डन, फलों का बागीचा, औषधीय उद्यान, मिश्रित प्रजाति का अलग खंड डिजिटल ओरिएंटेशन सेंटर शामिल हैं। इसे जापानी वनस्पतिशास्त्री अकीरा मियावाकी की तकनीक का इस्तेमाल करके विकसित किया गया है, जिससे कम समय में घने और देसी जंगल खड़े करने में मदद मिलती है।

को मजबूत करें, एक राष्ट्र के तौर पर देश को मजबूत करें। ये एकता तब मजबूत होगी, जब हर नागरिक एक जैसे कर्तव्य बोध से ये जिम्मेदारी संभालेगा। आज देश इसी कर्तव्य बोध को आगे रखकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र को लेकर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। आज देश के हर कोने में, हर गांव में, हर वर्ग के लिए और हर व्यक्ति के लिए बिना भेदभाव के एक जैसी नीतियां पहुंच रही हैं।" परेड से पहले पीएम मोदी ने सुरक्षा बल के जवानों को राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की शपथ दिलाई।

अंबाजी के आदिवासी बच्चों के म्यूजिकल बैंड की प्रस्तुति

केवड़िया में कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण अंबाजी के आदिवासी बच्चों के म्यूजिकल बैंड की प्रस्तुति थी। इस बैंड के सदस्य कभी अंबाजी मंदिर के बाहर भीख मांगते थे। पिछले महीने अपनी अंबाजी यात्रा के दौरान इन बच्चों की प्रस्तुति देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्रोत्साहित किया था। ऐसे असाधारण संगीत कौशल सीखने वाले इन आदिवासी बच्चों की कहानी काफी प्रेरक है। ये बच्चे कभी अपनी बुनियादी जरूरतों और शिक्षित होने का मौका पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे।

एकता नगर : पूरी दुनिया के लिए होगा आर्दश शहर

एकता नगर भारत के एक ऐसे मॉडल शहर के तौर पर विकसित हो रहा है, जो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अभूतपूर्व होगा। जब देश में पर्यावरण की रक्षा के लिए किसी मॉडल शहर की बात होगी या बिजली बचाने वाले एलईडी प्रकाशित किसी मॉडल शहर की बात होगी तो सबसे पहले एकता नगर का नाम आएगा। यहां सोलर पावर से चलने वाले क्लीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और विभिन्न प्रजातियों के जीव-जंतुओं का संरक्षण होगा। यहां का एकता मॉल, एकता नर्सरी, विविधता में एकता को प्रदर्शित करने वाला विश्व वन, एकता फेरी, एकता रेलवे स्टेशन, ये सारे उपक्रम, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की प्रेरणा हैं। अब एकता नगर में राजव्यवस्थाओं के त्याग को समर्पित एक म्यूजियम भी बनाया जाएगा।

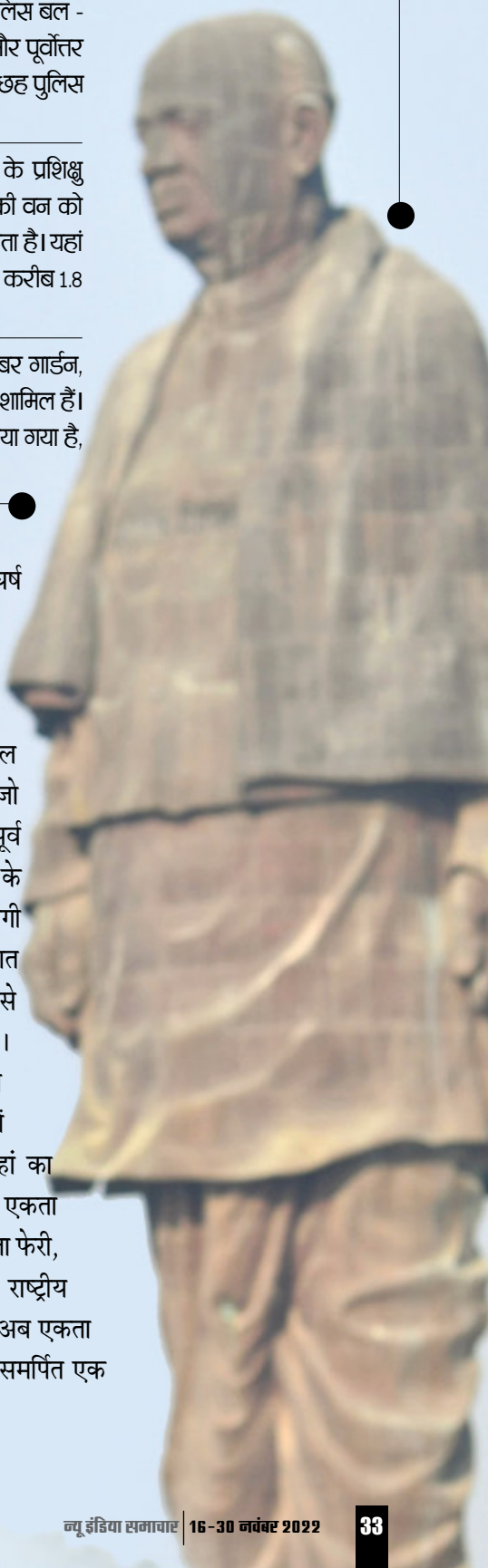

मिला सपनों का घर खुला गरिमा का द्वार

"अब हम खुशी-खुशी सीमेंट वाले पक्के घर में रह रहे हैं। हम जैसे गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने में सहयोग के लिए सरकार को धन्यवाद। अब मैं इस घर की गौरवान्वित मालिक हूं।" ओडीशा बलानगिर जिला के जीर्ण-शीर्ण घर में रहने वाली विधवा महिला शशि बारिक ने कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से पक्का घर बनाने में मिली मदद के बाद ये शब्द कहे थे। दिहाड़ी मजदूर बेटे की कमाई से 5 सदस्यीय परिवार का दिन में दो बार का भोजन भी मुश्किल से मिल पाता था। ऐसे में पक्के घर का सपना प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में मिली 1,30,000/- रुपये की सहायता से पूरा हुआ। शशि ने घर को जल्दी पूरा किया जिसके लिए सरकार ने प्रोत्साहन राशि भी दी...

झारखंड के गुमला जिले के चपका गांव में रहने वाली 59 वर्षीय बंधना उरांव एक कमरे के कच्चे मकान में रह रही थी। बरसात और सर्दी के मौसम में बहुत कठिनाई होती थी, बच्चे बीमार हो जाते थे। पक्का घर बनाना एक सपने जैसा था लेकिन पीएमएवाई-जी से मिली मदद के कारण सपना सच हुआ। बंधना ने परिवार के सदस्यों की मदद से अपना घर बनाया। अब बंधना प्रधानमंत्री आवास योजना से खुले 'गरिमा के द्वार' की वजह से परिवार के साथ नए घर में रह रही हैं। बंधना अब पक्के घर की मालकिन बन किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए आश्वस्त हैं। अब वह गांव में अन्य लोगों को भी अपना आवास कम से कम समय में पूरा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं।

योजना की सफलता के 5 मंत्र

01 सबसे पहले वंचित
योजना का लाभ गांव के उन गरीबों तक सबसे पहले पहुंचे जो घर की उम्मीद छोड़ चुके हैं।

02 पारदर्शिता
योजना में जाति-धर्म, वोट बैंक या सिफारिश को दूर रखकर 'गरीब है, हकदार है' को मंत्र मानें।

03 महिला सशक्तीकरण
योजना में सम्मान और स्वाभिमान को महिलाओं का अधिकार मानते हुए उन्हें घर का मालिक बनाने का प्रयास होना चाहिए।

04 तकनीक से निगरानी
घर के निर्माण की तकनीक के माध्यम से निगरानी हो।

05 मूलभूत जरूरतें शामिल
मकान चार दीवारें नहीं होती, जरूरत व स्थानीय शैली के हिसाब से घर बनाए जाएं।

मकान केवल ईंट, सीमेंट से तैयार ढांचा नहीं बल्कि इससे हमारी भावनाएं, हमारी आकांक्षाएं जुड़ी होती हैं। घर की चहारदीवारी हमें सुरक्षा तो प्रदान करती ही है, साथ ही हमारे अंदर एक बेहतर कल का भरोसा और विश्वास भी जगाती है।
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री।

ओडिशा की शशि बारिक हों या झारखंड की बंधना उरांव, सिर्फ इनका ही नहीं सभी का सपना होता है कि उनका अपना घर हो। क्योंकि जिसके सिर पर छत नहीं होती, कच्चे मकान या खंडहर हो चुके घर में रहता है या फिर किराए के मकान में रहकर बार-बार घर बदलना पड़ता है, वह घर की कीमत समझता है। लोगों के ऐसे ही सपने को सच करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर केंद्र सरकार ने शुरू की प्रधानमंत्री आवास योजना जिसने जरूरतमंद के लिए खोला गरिमा का द्वार और उन्हें मिला सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की 20 नवंबर, 2022 को छठी वर्षगांठ है और यह आवास उत्सव का दिन है।

मध्य प्रदेश के सागर जिले के सुधीर कुमार जैन ने प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस योजना को आवास विहीन परिवारों के लिए वरदान बताया। पहले सुधीर किराये के मकान में रह रहे थे और 6-7 बार मकान बदल चुके थे। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब में कहा, "अपनी छत, अपना घर पाने की खुशी अनमोल होती है। लाभार्थियों के जीवन में आए यह यादगार पल ही उन्हें राष्ट्र की सेवा में बिना थके, बिना रुके निरंतर कार्य करते रहने की प्रेरणा और ऊर्जा देते हैं। जब किसी को घर की चाबी मिलती है, तब एक सम्मानपूर्ण जीवन का द्वार खुलता है।"

देश में आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की शुरुआत 25 जून, 2015 से और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) 20 नवंबर, 2016 को शुरू की गई, जो पहली अप्रैल 2016 से प्रभावी है। 'सभी के लिए आवास' सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना मार्च, 2024 तक बढ़ा दी है। इस दौरान 1.56 करोड़ घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी और ग्रामीण में करीब 3.72

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

वर्ष 2016 में शुरु, ग्रामीण लोगों को पक्के घर उपलब्ध कराए जाते हैं, 2.55 करोड़ घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

8 वर्षों में ग्रामीण आवास को बढ़ावा पूर्ण रूप से निर्मित घरों की संख्या

वर्ष	संख्या
2006-2014	1.8 करोड़
2014-2022	2.55 करोड़

- घर का आकार 20 वर्ग मीटर (आईएवाई) से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर (पीएमएजी-वाई) करना।
- यूनिट सहायता 70/75 हजार रुपये (आईएवाई) से बढ़ाकर 1.20/1.30 लाख रुपये (पीएमएजी-वाई) करना।
- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत शौचालय के लिए 12 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी

- पीएम आवास योजना-शहरी विश्व की सबसे बड़ी आवासीय परियोजनाओं में से एक है।
- वर्ष 2015 में शुरु, जिसमें शहरी लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराए जाते हैं।
- 58.59 लाख घर निर्मित या सौंपे गए। नई प्रोद्योगिकियों का उपयोग करके बनाए जा रहे हैं 16 लाख घर।

उपलब्धियां

2004-14 बनाम **2015-22**

10X स्वीकृत मकानों की संख्या। 2014 तक 13.48 लाख थे, 2014 के बाद 122.69 लाख।

08X निर्मित मकानों की संख्या। 2014 तक 8.04 लाख थे,2014 से अब तक 63.65 लाख।

22X कुल निवेश, 2014 तक 0.38 लाख करोड़ रु.से बढ़कर 8.31 लाख करोड़ रु.।

10X केंद्रीय सहायता 0.20 लाख करोड़ रु. से बढ़कर 1.86 लाख करोड़ रु.।

674 करोड़ व्यक्ति दिवस या यूं कहें 2.40 करोड़ रोजगार सृजित हुए।

करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य है जिसमें करीब 3.5 करोड़ मकान बन चुके हैं। निर्मित मकानों में करीब 2.5 करोड़ मकान लाभार्थियों को सौंपे भी जा चुके हैं। यह घर ऐसे परिवारों को मिल रहे हैं जिनके पास अपना पक्का घर नहीं था। आधुनिक तकनीक वाले लाइट हाउस बनाए जा रहे हैं, जिसमें पहले चेन्नई और पिछले दिनों गुजरात के राजकोट में आधुनिक तकनीक से बने 1100 घरों की चाबी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों को सौंपी है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर एक अध्ययन किया है। उसमें सामने आया है कि पीएमएवाई में मिलने वाले पक्के निवास से लाभार्थी की सामाजिक स्थिति, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास स्तर, स्वामित्व और सुरक्षा की भावना, जीवन की समग्र गुणवत्ता के साथ सामाजिक-मनोवैज्ञानिक कल्याण पर गहरा प्रभाव पड़ा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो घर मिल रहे हैं, उसमें से 68 फीसदी परिवारों ने घर के अंदर आजीविका गतिविधियों के लिए जगह मिलने की बात कही है, जबकि 33 फीसदी सामान्य घरों में

मध्य प्रदेश में धनतेरस पर गृह प्रवेशम्

गृह प्रवेश से मिली सपनों को सच करने की नई ताकत

घर के बिना सभी संभावनाएं धुंधली होती हैं। किसी के गृह प्रवेश या घर मिलने का दिन नई खुशी, नए संकल्प, नए सपने और नई ऊर्जा का प्रतीक है। यही वजह है कि जब घर मिलता है तो उन्हें नई संभावनाएं दिखती हैं। मध्य प्रदेश के सतना में 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 4.5 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए आयोजित 'गृह प्रवेशम्' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, जहां धनतेरस पर सौंपी गई सपनों को सच करने वाले घर की चाबी...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, "देश में पहले गलत नीतियों के कारण लोगों को मजबूरी में आवासहीनता भी अगली पीढ़ी को सौंपनी पड़ती थी। हमें देश ने मौका दिया है, उस कुचक्र को तोड़ रहे हैं। हमारी सरकार हर गरीब को पक्की छत देने के लिए दिन-रात काम कर रही है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में घर बन रहे हैं।" मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 38 लाख घर स्वीकृत किए गए हैं जिनमें करीब 30 लाख घर बनाए जा चुके हैं। सरकार गरीबों की इच्छा, जरूरत को समझती है, इसलिए नए घर शौचालय, बिजली, पानी का कनेक्शन, गैस कनेक्शन से लैस हैं। देश का नेतृत्व अब अतीत से सबक लेकर नागरिकों के बुनियादी सुविधाओं की संपूर्णता पर काम कर रहा है। अतीत में बुनियादी सुविधाओं से इतने सारे लोग वंचित थे कि उनके पास और कुछ सोचने का समय ही नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, "हमने रास्ते बदल दिए, और घर के मालिकों को पूरा नियंत्रण उनके हाथ में दिया। पीएम आवास योजना अब सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण का माध्यम बन गई है। अब गरीब बुनियादी सुविधाओं से लैस होकर अपनी गरीबी कम करने के प्रयास कर रहे हैं।"

यह हमारी सरकार का बड़ा सौभाग्य है कि हम 3.5 करोड़ परिवारों के सबसे बड़े सपने को पूरा कर सके। यह आज का नया भारत है जहां गरीब धनतेरस पर अपने नए घरों में गृह प्रवेश कर रहे हैं। हम घरों की सुविधा से वंचित रहने के दुष्चक्र को तोड़ रहे हैं जो कई पीढ़ियों को प्रभावित करता था। -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

ही आजीविका गतिविधियों के लिए अलग से जगह थी। योजना के लाभार्थी ज्यादातर 30-41 वर्ष के हैं। इस उम्र में बेघर या कच्चे घर वालों को पक्का घर मिलता है तो वह आजीविका से संबंधित खोज पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 करोड़ लाभार्थियों में 74% से अधिक मकान महिला के नाम या संयुक्त रूप से पंजीकृत कराए गए हैं। महिलाओं को मिले घर के मालिकाना हक ने, घर के दूसरे आर्थिक फैसलों में भी महिलाओं की भागीदारी को मजबूत किया है। वहीं करोड़ों घर बनने से इस काम से जुड़े श्रमिक, मिस्त्री, बढ़ई, प्लंबर, फर्नीचर बनाने वाले उनको भी ढेर सारा काम मिलता है। रोजगार और उससे जुड़े कारोबार में वृद्धि हुई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके लिए आवास के संकल्प को कुछ इस तरह से दोहराते हैं- "गरीबों को अपना पक्का घर देने का यह अभियान सिर्फ एक सरकारी योजना मात्र नहीं है। ये गांव को, गरीब को विश्वास देने की प्रतिबद्धता है। गरीबी से लड़ने की हिम्मत देने की पहली सीढ़ी है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार पीएम आवास योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।"

पूर्व की 21 योजनाओं की गलतियों से निकली सफल योजना

देश में सरकारी आवासीय योजनाओं में घर तो पहले भी बनते थे, लेकिन उन योजनाओं को लेकर लोगों का अनुभव खराब रहा है। आजादी के बाद पहली आवासीय योजना, इंटीग्रेटेड सब्सिडाइज्ड हाउसिंग स्कीम फॉर इंडस्ट्रीयल वर्कर्स एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (1952) के नाम से आई थी। फिर हर 10-15 साल में योजनाओं में कुछ जुड़ता गया, नाम बदलते गए। इस तरह पीएमएवाई के पहले 21 योजनाएं आ चुकी थीं, लेकिन वंचितों के गरिमापूर्ण जीवन का लक्ष्य कभी पूरा नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में देश की बागडोर संभाली, तब पूर्व की 21 सरकारी आवासीय योजनाओं की गलत नीतियों, गलतियों से मुक्ति के साथ नई प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी और ग्रामीण के नाम से 'सबके लिए आवास' उपलब्ध कराने की शुरुआत की गई। ●

सरकारी दफ्तरों में फाइलों का अंबार खत्म

88 लाख वर्गफीट से अधिक जगह खाली

लंबे समय तक अटके मामले, फाइलों का बढ़ता अंबार और दफ्तरों के चक्कर काटते लोग, आमतौर पर भारतीयों के मन में सरकारी तंत्र को लेकर यही छवि बनी रही। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ देश की ही नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र की इस छवि को भी बदलने का काम किया है। यही कारण है कि देशभर के सरकारी विभागों में गांधी जयंती से 31 अक्टूबर तक चलाए गए विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 के जरिए न केवल 54 लाख से अधिक फाइलों की समीक्षा की गई, बल्कि लंबे समय से लंबित 4 लाख से अधिक प्रकरणों और शिकायतों का निपटारा कर 88 लाख वर्गफीट से अधिक जगह खाली कराई गई है। यही नहीं, स्वच्छता अभियान में फाइल व स्क्रैप का निस्तारण कर सरकार ने 364.53 करोड़ रुपये की कमाई भी की...

अटकाना, लटकाना, भटकाना और भूल जाना, लंबे समय तक सरकारी कार्यशैली का पर्याय बन चुके यह शब्द अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में निषेध हो चुके हैं, फिर बात चाहे विकास के प्रोजेक्ट की हो या फिर सरकारी दफ्तरों में आई शिकायतों या पेंडिंग फाइलों की। पिछले वर्ष पहली बार केंद्र सरकार ने सरकारी दफ्तरों में विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। इस वर्ष इसे और बड़े पैमाने पर अपनाते हुए गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 चलाया गया। यह बीते वर्ष के अभियान से करीब 15 गुना बड़ा था। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह के अनुसार इस अभियान अवधि में भारत के सुदूर इलाकों सहित संबद्ध/अधीनस्थ/क्षेत्रीय कार्यालयों पर विशेष ध्यान दिया गया। इस बार अभियान के तहत इस बार विशेष स्वच्छता अभियान को देश भर में कुल 99,633 जगहों पर चलाया गया है। इन जगहों पर लंबित 4,36,855 सार्वजनिक शिकायतों की फाइल की भी समीक्षा की गई और उनका निपटान किया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार देशभर के विभागों व मंत्रालयों में 54.5 लाख फाइलों की समीक्षा की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस अभियान में संसद सदस्यों के करीब 8784 संदर्भों व शिकायतों की भी समीक्षा कर उनका निस्तारण किया गया है।

इस अभियान के तहत विभिन्न विभागों व मंत्रालयों में पड़े कबाड़ का निपटान किया गया है। इन कबाड़ों को बेचकर सरकार को 364.53 करोड़ रुपये की आय हुई है। कबाड़ से कमाई करने के मामले में सैन्य मामलों का विभाग सबसे आगे है। यह कबाड़ बेचकर 212.76 करोड़ रुपये की कमाई के साथ शीर्ष पर है, इसके बाद कोयला मंत्रालय 48.51 करोड़ रुपये और रेल मंत्रालय 33.05 करोड़

99,633
जगहों पर चलाया गया अभियान।

4,36,855
सार्वजनिक शिकायतों की फाइलों की समीक्षा और निपटारा किया।

इस दौरान एक रिपोर्ट के अनुसार देशभर के विभागों व मंत्रालयों में 54.5 लाख फाइलों की समीक्षा की गई है।

बीते वर्ष 4 राष्ट्रपति भवन के बराबर जगह हुई थी खाली

बीते वर्ष भी सरकारी दफ्तरों में इसी तर्ज पर स्वच्छता अभियान चलाया गया था। तब लंबित फाइलों और स्क्रैप के निपटारे के बाद राष्ट्रपति भवन के फ्लोर एरिया के मुकाबले करीब 4 गुना जगह खाली हुई थी। राष्ट्रपति भवन का फ्लोर एरिया करीब 2 लाख वर्ग फीट है, जबकि निपटारे के बाद करीब 9 लाख वर्ग फीट से अधिक की जगह खाली हुई थी। उस समय 3 लाख 28 हजार लोक शिकायतों पर काम कर 3 लाख 3 हजार शिकायतों का निपटारा किया गया था। वहीं, सांसदों की 11057 चिट्ठियों में से 8282 को निपटारा करने के साथ 834 में से 685 नियमों और प्रक्रियाओं को सरल किया गया था।

रुपये है।

ऐसे चला अभियान

विशेष अभियान 2.0, आकार और पैमाने में समग्र था, जिसमें हजारों अधिकारियों और नागरिकों की व्यापक भागीदारी देखी गई, जिन्होंने सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता के लिए एक आंदोलन चलाया।

डाक विभाग ने 24000 डाकघरों में स्वच्छता अभियान चलाया है, रेल मंत्रालय ने 9374 रेलवे स्टेशनों में, रक्षा विभाग ने 5922 अभियान स्थलों में और गृह मंत्रालय ने 11559 अभियान स्थलों में स्वच्छता अभियान चलाया। 16 मंत्रालयों/विभागों ने 1000 से अधिक अभियान स्थलों में विशेष अभियान 2.0 का संचालन किया, 31 मंत्रालयों/विभागों ने 100 से अधिक अभियान स्थलों में विशेष अभियान 2.0 में आयोजित किया था। विशेष अभियान 2.0 की प्रगति की निगरानी एक समर्पित पोर्टल www.pgportal.gov.in/scdpm22 पर दैनिक आधार पर की गई। सभी मंत्रालयों/विभागों में 215 नोडल अधिकारी/उप-नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। भारत सरकार के सचिवों द्वारा साप्ताहिक आधार पर विशेष अभियान 2.0 की समीक्षा की गई। विशेष अभियान 2.0 की प्रगति को सोशल मीडिया में व्यापक रूप से मंत्रालयों/विभागों द्वारा 67,000 से अधिक सोशल मीडिया ट्वीट के साथ सूचित किया गया है। मंत्रालयों/विभागों द्वारा पत्र सूचना कार्यालय के माध्यम से 127 वक्तव्य जारी किए गए। ●

364.53

करोड़ रुपये की आय हुई इन कबाड़ों को बेचकर। 212.76 करोड़ रुपये की कमाई के साथ शीर्ष पर है सैन्य मामलों का विभाग, इसके बाद कोयला मंत्रालय 48.51 करोड़ रुपये और रेल मंत्रालय 33.05 करोड़ रुपये है।

ऐसे चला अभियान...

डाक विभाग

24,000

डाकघरों में स्वच्छता अभियान चलाया।

रेल मंत्रालय

9,374

रेलवे स्टेशनों पर चलाया अभियान।

रक्षा विभाग ने 5,922 अभियान स्थलों में और गृह मंत्रालय ने 11,559 अभियान स्थलों में स्वच्छता अभियान चलाया।

अब ई-वॉलेट में रखिए e₹

होलसेल ई-रुपी लांच, रिटेल जल्द

भारत, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। देश ने 2021-2022 में 88.4 अरब से अधिक डिजिटल भुगतान लेनदेन किए थे जबकि चालू वित्त वर्ष के शुरुआत तिमाही के आंकड़े बताते हैं कि अब हर दिन औसतन 28.8 करोड़ डिजिटल लेनदेन भारतीय कर रहे हैं। इसी डिजिटल और पारदर्शी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर को देश की पहली डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी-थोक (ई-डब्ल्यू) का पायलट प्रोजेक्ट किया लांच...

देश के डिजिटल e₹-W लांच के साथ ही रिजर्व बैंक दुनिया के उन कुछ केंद्रीय बैंकों में शामिल हो गया है जिसने यह पहल की है। पायलट प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल सरकारी प्रतिभूतियों के निपटारे में किया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के आधार पर भविष्य में अन्य बड़ी राशि के लेन-देन और सीमा पार भुगतान को लेकर भी पायलट प्रोजेक्ट किए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट में डिजिटल करेंसी की घोषणा की थी।

डिजिटल e₹ फिजिकल रुपये और यूपीआई के मुकाबले अलग है। फिजिकल करेंसी सरकार को छापनी होती है, प्रयोगकर्ता को अपने पास रखना होता है। इसी तरह यूपीआई से लेनदेन के लिए बैंक खाते में पैसे रखने होते हैं जबकि डिजिटल e₹ में प्रिंटिंग और उसके खराब होने की आशंका नहीं है। ई-वॉलेट में स्टोर किया जा सकता है। हालांकि डिजिटल e₹ से लेनदेन के लिए बैंक खाते से या फिजिकल करेंसी के तौर पर बैंक में पैसे जमा कराने होंगे।

चुनिंदा लोकेशन से शुरू होगा रिटेल e₹

- आरबीआई ने घोषणा की है कि जल्द ही रिटेल **e₹** का पायलट भी लांच किया जाएगा। इसकी शुरुआत पहले ऐसे चुनिंदा स्थानों से होगी जहां एक दायरे वाले ग्राहक और व्यापारी शामिल होंगे।

होलसेल और रिटेल के लिए अलग-अलग e₹

- आरबीआई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (**CBDC**) होलसेल और रिटेल दोनों अलग-अलग करेंसी होगी। यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है।
- होलसेल करेंसी का इस्तेमाल बैंकिंग प्रणाली जैसे वित्तीय संस्थान करेंगे। रिटेल ई-रुपी का प्रयोग लेनदेन में लोग दैनिक जरूरतों में करेंगे। फिजिकल करेंसी नोट के रूप में जेब में होता है जबकि ई-रुपी वॉलेट में रहेगा।

e₹ UPI PREPAID e-VOUCHER

डिजिटल इकोनॉमी को बल मिलेगा। आरबीआई ही इसे नियंत्रित करेगी। फिनटेक के क्षेत्र में अवसरों के नए द्वार खोलेगा। कैश को प्रिंट करने, हैंडल करने और वितरण का बोझ भी कम होगा। -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री।

शुरुआत में ये बैंक हैं शामिल

- पायलट प्रोजेक्ट में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी बैंक शामिल हैं।

e₹ के फायदे

- डिजिटल **e₹** फिजिकल का ही डिजिटल स्वरूप है। डिजिटल रिस्क फ्री, **e₹** को फिजिकल करेंसी से एक्सचेंज कर सकेंगे।
- नगदी पर निर्भरता घटेगी, नोट छापने का खर्च बचेगा। ग्लोबल डिजिटल पेमेंट सिस्टम के निर्माण में भी आसानी होगी। फेक करेंसी की समस्या से निजात दिलाने में मदद करेगा। ●

90वीं इंटरपोल महासभा में पीएम मोदी का संबोधन

स्थानीय हितों के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान

वेदों के एक श्लोक में कहा गया है- आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः अर्थात सभी दिशाओं से उत्तम विचारों को आने दें। इंटरपोल की अवधारणा भी भारतीय दर्शन के विभिन्न पहलुओं के साथ जुड़ती है। इंटरपोल का आदर्श वाक्य है, 'एक सुरक्षित दुनिया के लिए पुलिस को जोड़ना।' एक ऐसे समय में जब अधिकांश राष्ट्र व समाज अंतर्मुखी होते जा रहे हैं तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 अक्टूबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित किया और स्थानीय हितों के लिए वैश्विक सहयोग का किया आह्वान...

कानून के कार्यान्वयन के दर्शन को प्राचीन भारतीय दार्शनिक चाणक्य ने सबसे अच्छी तरह समझाया है। आन्वीक्षकी त्रयी वार्तानां योग-क्षेम साधनो दण्डः। तस्य नीतिः दण्डनीतिः अलब्धलाभार्था, लब्धपरिरक्षणी, रक्षितविवर्धनी, वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी च। इसका अर्थ है, किसी समाज का भौतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण कानून के कार्यान्वयन के माध्यम से सुनिश्चित होता है। चाणक्य के अनुसार, कानून का कार्यान्वयन जो हमारे पास नहीं है उसे हासिल करने, जो हमारे पास है उसकी रक्षा करने, जो हमने संरक्षित किया है उसे बढ़ाने और सबसे सुपात्र लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। यह कानून के कार्यान्वयन का एक समावेशी दृष्टिकोण है। दुनिया भर में पुलिस बल न केवल लोगों की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि सामाजिक कल्याण को भी आगे बढ़ा रहे हैं। वे किसी भी संकट के खिलाफ समाज की प्रतिक्रिया की अग्रिम पंक्ति में भी मौजूद होते हैं। यह कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे अधिक दिखाई दिया। 90वीं इंटरपोल महासभा के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "दुनिया भर में, पुलिसकर्मियों ने लोगों की मदद करने के लिए अपनी जान को जोखिम में

डाला। उनमें से कइयों ने तो लोगों की सेवा में अपना जीवन भी बलिदान कर दिया। मैं उन्हें नमन करता हूं। दुनिया थम जाए, तब भी उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी नहीं खत्म होती। महामारी के दौरान भी इंटरपोल सातों दिन चौबीसों घंटे अपना कर्तव्य निभाता रहा।" हमारे पुलिस बल न केवल लोगों की रक्षा करते हैं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की भी सेवा करते हैं। भारत के स्वतंत्र, निष्पक्ष और व्यापक चुनावों की व्यवस्था पर ही अगर नजर डालें तो चुनावों में लगभग 900 मिलियन मतदाताओं की व्यवस्था शामिल है। यह उत्तर और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपों की कुल जनसंख्या के करीब है। लगभग 23 लाख पुलिस कर्मियों को चुनाव में सहायता के लिए तैनात किया जाता है। विविधता और लोकतंत्र को कायम रखने में भारत दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हमारे पुलिस बल संविधान द्वारा किए गए वादे के अनुसार लोगों की विविधता और अधिकारों का सम्मान करते हुए काम करते हैं।" प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शिकार और संगठित अपराध जैसे कई उभरते हानिकारक वैश्वीकृत खतरों के बारे में भी याद दिलाया। उन्होंने कहा, "इन खतरों के परिवर्तन की गति पहले की तुलना में तेज है। जब खतरे वैश्विक हों, तो प्रतिक्रिया सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं हो सकती! समय आ गया है कि दुनिया इन खतरों को हराने के लिए एक साथ आए।" एक सुरक्षित और संरक्षित दुनिया हमारी साझा जिम्मेदारी है। जब अच्छी ताकतें सहयोग करती हैं, तो अपराध की ताकतें काम नहीं कर सकतीं। इस पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "पुलिस और कानून का अमल कराने वाली एजेंसियों को सहयोग बढ़ाने के लिए प्रक्रिया और प्रोटोकॉल तैयार करने की आवश्यकता है। भगोड़े अपराधियों के लिए रेड कॉर्नर नोटिस तेज करके इंटरपोल मदद कर सकता है।" इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नासेर अल रईसी एवं महासचिव जर्गन स्टॉक और सीबीआई निदेशक भी मौजूद रहे। ●

दिल्ली में 18 से 21 अक्टूबर तक 90वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन

- इंटरपोल की 90वीं महासभा 18 से 21 अक्टूबर तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित की गई। बैठक में 195 इंटरपोल सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए जिनमें देशों के मंत्री, पुलिस प्रमुख, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल थे। महासभा इंटरपोल की सर्वोच्च नियंत्रक संगठन है और इसके कामकाज से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए वर्ष में एक बार बैठक होती है।
- लगभग 25 वर्षों के अंतराल के बाद भारत में इंटरपोल महासभा की बैठक हुई। यह पिछली बार 1997 में हुई थी।
- भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के समारोह के साथ नई दिल्ली में 2022 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी करने के भारत के प्रस्ताव को महासभा द्वारा जबर्दस्त बहुमत से स्वीकार कर लिया गया था।
- यह आयोजन पूरी दुनिया को भारत की कानून-व्यवस्था की प्रणाली के सर्वोत्तम तौर-तरीकों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। इस मौके पर भारत ने दुनिया के सामने विधि एवं व्यवस्था से जुड़ी अपनी सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को प्रदर्शित किया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 90वीं इंटरपोल महासभा के आयोजन को यादगार बनाने के लिए एक स्मारक डाक टिकट और 100 रुपये का सिक्का जारी किया।

इंटरपोल के 2023 में पूरे होंगे 100 साल

भारतीय पुलिस बल 900 से अधिक राष्ट्रीय और 10,000 राज्य कानूनों को लागू करते हैं। विविध भाषाओं और परंपराओं वाले देश में यह एक बेहद कठिन कार्य है।

2023 में इंटरपोल अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करेगा। ऐसे में यह जश्न और चिंतन करने का सबसे अच्छा समय है।

कानूनी ढांचे में परिवर्तन के बावजूद इंटरपोल ने पिछले 99 वर्षों में 195 देशों के पुलिस संगठनों को आपस में जोड़ा है।

गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर : सहकारी संघवाद को मजबूती

देश की बेहतरी के लिए राज्यों का एक साथ काम करना संविधान की भावना भी है और हमारा दायित्व भी। इसी कड़ी में हरियाणा के सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर आयोजित किया गया जो सहकारी संघवाद का एक उत्तम उदाहरण है। इस चिंतन शिविर का उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा के लिए 'विजन 2047' और विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषित 'पंच प्राण' के क्रियान्वयन की कार्य योजना तैयार करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अक्टूबर को इस शिविर को संबोधित किया जिसमें उन्होंने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, साइबर अपराध प्रबंधन, महिला सुरक्षा आदि पर की चर्चा...

हरेक राज्य एक-दूसरे से सीखें और प्रेरणा लें, देश की बेहतरी के लिए मिलजुल कर काम करें, ये संविधान की भावना भी है और देश-राज्यों के प्रति हमारा दायित्व भी है। संविधान में भले कानून और व्यवस्था राज्यों का दायित्व है, लेकिन ये देश की एकता-अखंडता के साथ भी उतने ही जुड़े हुए हैं। राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतिन शिविर को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "मुझे विश्वास है अगर हम मिलकर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हर चुनौती हमारे सामने छोटी हो जाएगी। हर राज्य को साथ मिलकर काम करना होगा। जब देश का सामर्थ्य बढ़ेगा तो देश के हर नागरिक, हर परिवार का सामर्थ्य बढ़ेगा। यही तो सुशासन है, जिसका लाभ देश के हर राज्य को समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है।" बीते वर्षों में भारत सरकार के स्तर पर कानून व्यवस्था से जुड़े जो सुधार हुए हैं, उन्होंने पूरे देश में शांति का वातावरण बनाने में मदद की है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "पंच प्राण देश के हर राज्य में सुशासन की प्रेरणा होने चाहिए।" बेहतर कानून व्यवस्था पंच प्राण के संकल्प को और मजबूत बनाती है, साथ ही सुशासन के माध्यम से राज्यों के सामर्थ्य को विराट विस्तार करने का अवसर प्रदान करती है।

चिंतिन शिविर में छह सत्रों में विभिन्न विषयों पर की गई चर्चा

- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 27 और 28 अक्टूबर को राज्यों के 'गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर' की अध्यक्षता की। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अक्टूबर को चिंतन शिविर को संबोधित किया। चिंतिन शिविर में छह सत्रों में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।

- दो दिवसीय चिंतन शिविर में गृह सचिव और राज्यों के पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक ने भी भाग लिया।
- गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में साइबर अपराध प्रबंधन के लिए ईको-सिस्टम विकसित करने, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, आपराधिक न्याय प्रणाली में आईटी के बढ़ते उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन और तटीय सुरक्षा एवं अन्य आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विमर्श किया गया।
- देश में महिलाओं की सुरक्षा और उनके लिए सुरक्षित वातावरण बनाने पर विशेष बल दिया गया। शिविर का उद्देश्य उपर्युक्त क्षेत्रों में राष्ट्रीय नीति निर्माण और बेहतर योजना व समन्वय को सुगम बनाना भी था। ●

एकजुटता के मंत्र के साथ

'एक भारत, श्रेष्ठ भारत'

की भावना को जिन्होंने दी मजबूती

भारत को स्वाधीनता आसानी से नहीं मिली, बल्कि इसके लिए देश को भारी कीमत चुकानी पड़ी। पराधीनता के समय ब्रिटिश सरकार का अत्याचार जब भारतीय जनमानस के धैर्य की सीमा को लांघने लगा तो आजादी के दीवानों ने अंग्रेजों को सबक सिखाने की ठानी और राष्ट्र की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए स्वाधीनता हासिल की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो देशभक्ति का जज्बा देखा गया, वह अभूतपूर्व था। इस दौरान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। भारत 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहा है जो आज की पीढ़ी के लिए 'संस्कार उत्सव' है। साथ ही यह हमारे देश के सपनों को साकार करने के लिए संकल्प से सिद्धि का समय भी है। 'आजादी का अमृत महोत्सव' श्रृंखला की इस कड़ी में कहानी ऐसे ही नायकों की जिन्होंने एकजुटता के मंत्र के साथ 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को दी मजबूती...

करतार सिंह सराभा

जिनकी तस्वीर अपनी जेब में रखते थे भगत सिंह

जन्म : 24 मई,1896, मृत्यु : 16 नवंबर, 1915

प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह करोड़ों भारतीयों के हीरो हैं, लेकिन वह खुद जिस व्यक्ति से प्रेरणा लेकर क्रांतिकारी बने उस महान शख्सियत का नाम था करतार सिंह सराभा। कहा जाता है कि भगत सिंह, करतार सिंह साराभा की फोटो अपनी जेब में रखते थे। महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी करतार सिंह, देश की खातिर मात्र 19 वर्ष की उम्र में ही फांसी पर चढ़ कर शहीद हो गए थे। करतार सिंह सराभा का जन्म 24 मई,1896 को पंजाब के सराभा गांव में हुआ था। करतार सिंह का गांव कई बार पड़े सूखे से तबाह हो गया था और बेहतर अवसरों की खोज में वे 1912 में सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। वे बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में शिक्षा पूरी करना चाहते थे। अमेरिका में विशेषरूप से भारतीय लागों के साथ अमेरिकी नागरिकों की शत्रुता पर उन्हें बहुत क्रोध आया। कैलिफोर्निया में सराभा को उपनिवेश भूमि से आने वाले लोगों के अपमान का पूरा अहसास हुआ। ऐसे में उन्होंने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के बारे में आक्रोश प्रकट करना शुरु कर दिया। 1913 में ओरेगॉन में गदर पार्टी की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ कर अपने लोगों की प्रतिष्ठा बहाल करना था। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। सराभा ने गदर पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरु कर दिया। उन्होंने गदर अखबार के पंजाबी संस्करण की जिम्मेदारी संभाली और वहां रह रहे भारतीयों को जागरूक करने के लिए उसका प्रकाशन शुरु कर दिया। जुलाई 1914 में यूरोप जब प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया तो गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे ब्रिटिश सत्ता पर आक्रमण का अवसर समझा। गदर पार्टी ने भारतीयों को संगठित करने की योजना बनाई। करतार सिंह गदर पार्टी के उन कार्यकर्ताओं में शामिल थे जो 1914 में भारत वापस आ गए। भारत आते ही अंग्रेजों ने गदर पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इससे विचलित हुए बिना करतार सिंह और रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों ने पंजाब की छावनियों में सैनिकों को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करना शुरु कर दिया। लेकिन गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं की योजना पर अमल होने से पहले ही अंग्रेजों को भनक लग गई और करतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध इस मुकदमे के तहत लाहौर में कई सुनवाई हुई और पकड़े गए कार्यकर्ताओं पर विद्रोह में शामिल होने के आरोप लगाए गए। करतार सिंह सराभा ने अदालत में माफी नहीं मांगी और गर्व से कहा, "अंग्रेजों के विरुद्ध अपने लोगों को एकजुट करना मेरा कर्तव्य है।" उनकी अटल देशभक्ति ने जजों को बेहद नाराज कर दिया। 16 नवंबर, 1915 को लाहौर सेंट्रल जेल में 19 वर्ष के सराभा और उनके साथी विष्णु गणेश पिंगले को फांसी दे दी गई।

ग्रामीण स्वच्छता

की अमृत यात्रा

1947 से पहले देश आजादी के लिए लड़ा तो अब देश उन बुराइयों के खिलाफ खड़ा हुआ है, जिनकी वजह से भारत पिछड़े देशों में गिना जाता था। ऐसी ही एक बुराई है गंदगी, जिसे बुराई तो सबने माना लेकिन इसके बावजूद 1981 तक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज मात्र 1 फीसदी ही था। इसी बुराई को मिटाने के लिए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था स्वच्छ भारत मिशन...और इसका परिणाम अब सबके सामने है।

- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया।
- इस मिशन के तहत 6 लाख से अधिक गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया।
- भारत की ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 1981 में सिर्फ 1% थी, जो 2019 में बढ़कर शत-प्रतिशत हो गई।
- स्वच्छता कवरेज से तात्पर्य जनसंख्या के उस प्रतिशत से है, जिनके घरों में शौचालय है।

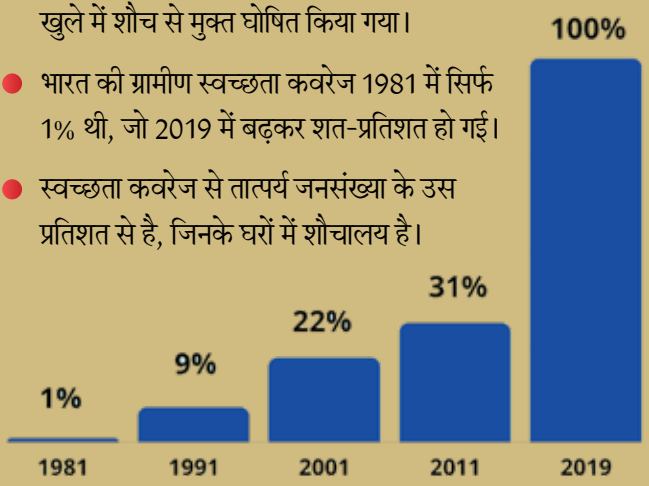

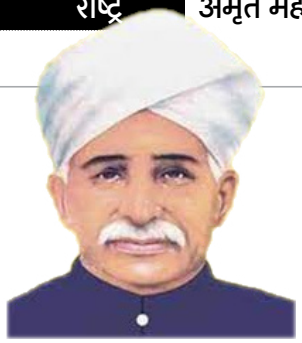

दीनबंधु सर छोटूराम

अंग्रेजों से भिड़ने वाले किसानों के मसीहा

जन्म : 24 नवंबर, 1881, मृत्यु : 9 जनवरी, 1945

अंग्रेजों से भिड़ने वाले और किसानों के मसीहा के रूप में पहचान रखने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी दीनबंधु सर छोटूराम का जन्म 24 नवंबर, 1881 को हुआ था। वर्तमान हरियाणा में झज्जर के एक छोटे से गांव गढ़ी सांपला में बहुत ही साधारण परिवार में जन्मे छोटूराम बचपन से ही दृढ़ इच्छाशक्ति के धनी थे। कहा जाता है कि एक बार एक साहूकार ने कर्ज देने की बजाय चौधरी छोटूराम को पटवारी बनने की सलाह दी थी। लेकिन साहूकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिसको वो पटवारी बनने का सुझाव दे रहे हैं, वो एक दिन हजारों पटवारियों की किस्मत तय करने वाला है। सिर्फ और सिर्फ अपने सामर्थ्य के बल पर संघर्ष करते हुए चौधरी साहब पंजाब के राजस्व मंत्री के पद तक पहुंचे थे। 1916 में जब रोहतक में कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ तो छोटूराम इसके अध्यक्ष बने लेकिन बाद में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से असहमत होकर इससे अलग हो गए। उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया और 1937 के प्रोवेंशियल असेंबली चुनावों में उनकी पार्टी को जीत मिली। छोटूराम विकास व राजस्व मंत्री बने। उनकी दूरदृष्टि को देखते हुए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कहा था, "चौधरी छोटूराम न सिर्फ ऊंचे लक्ष्य तय करना जानते हैं बल्कि उन लक्ष्यों को हासिल कैसे किया जाए इसका मार्ग भी उन्हें अच्छी तरह पता था।" उनका नाम देश के उन समाज सुधारों में शामिल है जिन्होंने भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो किसानों, मजदूरों, वंचितों, शोषितों की बुलंद और मुखर आवाज थे। वो समाज में भेद पैदा करने वाली हर शक्ति के सामने डटकर खड़े होने वाले व्यक्ति थे। कृषि से जुड़ी समस्याओं, किसानों, छोटे उद्यमियों के सामने आने वाली विपत्तियों, चुनौतियों को उन्होंने बहुत करीब से देखा और समझा था। कहा जाता है कि पश्चिम और उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में उनका प्रभाव इतना व्यापक था कि अंग्रेज प्रशासक भी उनकी बात मानने के इंकार करने से पहले सौ बार सोचने के लिए मजबूर होते थे। इतना ही नहीं, भाखड़ा बांध की असली सोच छोटूराम की ही थी। उन्होंने ही बिलासपुर के राजा के साथ भाखड़ा बांध प्रोजेक्ट के लिए हस्ताक्षर किए थे। इस बात का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लोगों को, किसानों को आज भी लाभ मिल रहा है। छोटूराम ने जिस प्रकार किसानों, मजदूरों के उत्थान के लिए संपूर्णता के साथ सोचा, उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भी बीज से बाजार तक की एक सशक्त व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रही है। किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले, मौसम की मार से किसानों को सुरक्षा कवच मिले, आधुनिक बीज मिले, पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिले, सिंचाई की उचित व्यवस्था मिले, मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे, इस पर निरंतर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अक्टूबर 2018 को हरियाणा के सांपला में छोटूराम की प्रतिमा का अनावरण किया था। इस अवसर पर उन्होंने कहा था, "चौधरी छोटूराम उन सामाजिक सुधारकों में से एक थे जिन्होंने भारत में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया।" उन्होंने छोटूराम को पीड़ितों और वंचितों के उद्धार के लिए निरंतर कार्य करने वाली शख्सियत के रूप में वर्णित किया।

शांति घोष जिन्होंने 15 साल की उम्र में ब्रिटिश अधिकारी को मारी गोली

जन्म : 22 नवंबर 1916, मृत्यु : 28 मार्च 1989

भारत के स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी वीरांगना शांति घोष का जन्म 22 नवंबर 1916 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। शांति के पिता देबेंद्रनाथ घोष कोमिला के विक्टोरिया कॉलेज में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और मातृभूमि के लिए समर्पण की भावना शांति में घर से ही जागृत हुई। शांति घोष, कोमिला में छात्र संघ की संस्थापक सदस्य थीं। वे क्रांतिकारी संगठन जुगांतर पार्टी में शामिल हो गईं। इस पार्टी का मूल उदेश्य क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना था। ऐसे में, संगठन ने तलवारबाजी और लाठी चलाने के साथ ही शांति को अन्य शस्त्रों का भी प्रशिक्षण दिया। बाद में उन्हें एक विशेष अभियान के लिए चुना गया।

मीराबेन महात्मा गांधी की अनुयायी महिला जिन्होंने भारत की आजादी के संघर्ष में लिया भाग

जन्म : 22 नवंबर 1892, मृत्यु : 20 जुलाई 1982

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुयायी पूरी दुनिया में रहे हैं लेकिन उनकी एक अनुयायी ऐसी भी थी जिसने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए धन-दौलत ही नहीं, बल्कि देश भी छोड़ दिया था। वो अनुयायी कोई और नहीं बल्कि मीराबेन थी जिसका असली नाम मेडेलीन स्लेड था। वह ब्रिटिश नेवी ऑफिसर एडमंड स्लेड की बेटी थीं। उनका जन्म 22 नवंबर 1892 को ब्रिटेन में हुआ था। महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों से प्रभावित होकर उन्होंने भारत को ही अपना घर बना लिया। मीराबेन ने मानव विकास, महात्मा गांधी के सिद्धांतों की उन्नति और स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मूलरूप से भले ही वह एक अंग्रेज थीं, लेकिन उनका दिल हिंदुस्तान की आजादी के लिए धड़कता था। वे करीब 34 वर्षों तक भारत में रहीं। मीराबेन 7 नवंबर, 1925 को अहमदाबाद आईं जहां महादेव देसाई, वल्लभभाई पटेल और स्वामी आनंद ने उनका स्वागत किया था। महात्मा गांधी ने उन्हें साबरमती आश्रम में रहने की अनुमति दी और उन्हें मीराबेन नाम दिया। तब से महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में वह हमेशा उनके साथ रहने लगीं। कहा जाता है कि बापू, उन्हें अपनी बेटी मानते थे। भारत में प्रवास के आरंभिक वर्षों के दौरान मीराबेन ने हिंदी सीखी और भारत को जानने-समझने के लिए गांवों की यात्रा की। जल्द ही, वे महात्मा गांधी के भरोसेमंद लोगों में से एक बन गई। 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह गांधीजी के साथ लंदन गई थी। लंदन से वापस भारत आने के बाद वह खादी के प्रचार-प्रसार में लग गयीं और इसके लिये पूरे देश की यात्रा की। मीराबेन सादी धोती पहनती, सूत कातती और गांव-गांव घूमती। वह महात्मा गांधी के संदेशों का पालन करती रहीं और वह अहिंसा के संदेश के प्रचार-प्रसार में सक्रिय रहीं।

उन्होंने यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका में हजारों लेख लिखे। उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी उन्हें हिरासत में रखा गया था। अंग्रेजों ने उन पर भारत में रहते हुए यूरोप और अमेरिका में सूचना भेजने का भी आरोप लगाया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। मीराबेन 9 अगस्त 1942 से लेकर 6 मई 1944 तक महात्मा गांधी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ-साथ उनके सचिव महादेवभाई देसाई, प्यारेलाल नायर, सरोजनी नायडू और डॉ. सुशीला नायर के साथ पुणे के आगा खान पैलेस में कैद रहीं। उन्होंने 1947 में ऋषिकेश के निकट एक आश्रम की स्थापना की। अगले 11 वर्ष के दौरान उन्होंने भारत के विभिन्न प्रदेशों की यात्रा की, सामुदायिक परियोजनाएं चलाईं और पर्यावरण के मुद्दों पर कार्य किया। 18 जनवरी, 1959 को मीराबेन इंग्लैंड चली गई। उसके एक वर्ष बाद वे वियना चली गई और जीवनपर्यंत वहीं रहीं। भारत सरकार ने 1982 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 20 जुलाई 1982 को मीराबेन का निधन हो गया।

15 वर्षीय शांति घोष अपनी हमउम्र सुनीति चौधरी के साथ 14 दिसंबर 1931 को कोमिला के जिला मजिस्ट्रेट चार्ल्स जेफ्री बकलैंड स्टीवंस को क्रिसमस से पहले कैंडी और चॉकलेट देने के बहाने उनके कार्यालय गईं। स्टीवंस ने कैंडी खाई और कहा, 'ये स्वादिष्ट हैं!' इतना सुनते ही शांति घोष और सुनीति चौधरी ने शॉल के नीचे छिपाई गई पिस्तौल बाहर निकाली और कहा, 'अच्छा, यह कैसी है मिस्टर मजिस्ट्रेट?' और इसके साथ ही उन्होंने मजिस्ट्रेट पर गोली चला दी। गोली लगने के कारण मजिस्ट्रेट की थोड़ी देर में मौत हो गई। इस घटना के बाद शांति घोष और सुनीति चौधरी को मजिस्ट्रेट की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया। कम उम्र होने के कारण दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और खड़गपुर के हिजली डिटेंशन कैंप भेज दिया गया। यही नहीं, जेल में उन्हें उनकी साथी सुनीति से अलग बैरक में रखा गया। हालांकि, 1939 में महात्मा गांधी और ब्रिटिश सरकार के बीच वार्ता के परिणामस्वरूप, उन्हें सात साल की सजा काटने के बाद रिहा कर दिया गया। अपनी रिहाई के बाद, उन्होंने बंगाली महिला कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई पूरी की। देश की स्वाधीनता के बाद वह राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में निरंतर जुड़ी रहीं। वे 1952 से 1962 और फिर 1967 से 1968 तक पश्चिम बंगाल विधान परिषद की सदस्य रहीं। वे 1962 से 1964 तक पश्चिम बंगाल विधान सभा की सदस्य भी रहीं। उन्होंने 'अरुण बहनी' नाम से बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा भी लिखी है। 28 मार्च 1989 को अपने निधन तक शांति घोष, देश की भलाई के लिए निरंतर काम करती रहीं। ●

PMO India @PMOIndia

India is scaling new heights with @makeinindia and Aatmanirbhar Bharat Abhiyan. The initiatives have led to a significant rise in number of exports.

रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India @DefenceMinIndia

आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, राष्ट्र को 75 infrastructure projects समर्पित करना, BRO की नई सोच, नया उत्साह, और देश के प्रति ज़िम्मेदारी की भावना को दिखाता है। BRO ही नहीं, बल्कि मैं देख रहा हूँ, कि पिछले कुछ सालों में समूचे देश की सोच में एक बड़ा परिवर्तन आया है: RM

Amit Shah @AmitShah

हम भारत की किसी भी भाषा व बोली को लुप्त नहीं होने देंगे।

मेरा युवाओं से आग्रह है कि आप कोई भी भाषा सीखो मगर अपनी मातृभाषा कभी मत छोड़ना क्योंकि व्यक्ति की क्षमता बढ़ाने, निर्णय पर पहुंचने व विश्लेषण की प्रक्रिया करने का सबसे अच्छा माध्यम उसकी मातृभाषा होती है।

Nitin Gadkari @nitin_gadkari

Connecting Ashtalakshmi with Prosperity under the leadership of PM Shri @narendramodi Ji.

The project for 4-Laning of Jorabat Shillong (Barapani) stretch in Meghalaya, was developed on BOT (Annuity) mode and inaugurated on 1st May 2015.
#PragatiKaHighway #GatiShakti

Piyush Goyal @PiyushGoyal

A reason why India is being called a global bright spot is the strength of its core industries.

Output of 8 core industries in September grew 7.9%

Bhupender Yadav @byadavbjp

Congratulations all!

Happy to inform that Ranipur Tiger Reserve in Uttar Pradesh has become the 53rd tiger reserve of India.

Spread over 529.36 sq km (core area 230.32 sq km & buffer area 299.05 sq km), the new tiger reserve will strengthen our tiger conservation efforts.

प्रधानमंत्री मोदी ने किया दीपोत्सव का शुभारंभ, 37 घाटों पर जले 15.76 लाख दीये, विश्व रिकॉर्ड बना

दीपों से 'दिव्य' अयोध्या जी, भावनाओं से 'भव्य' अयोध्या जी

पीएम मोदी ने किए रामलला के दर्शन

सरयू तट पर उतरा 'स्वर्गलोक'

पीएम ने कहा

सामर्थ्य के बिना हासिल नहीं की जा सकती शांति

प्रधानमंत्री मोदी ने करगिल में जवानों संग मनाई दिवाली

जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए सुनाई कविता

वडोदरा से पीएम का नया मंत्र, मेक फॉर द ग्लोब

पहले प्राइवेट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की नींव रखी

2019 के बाद कश्मीर में 30,000 जॉब

सोलर सेक्टर की उपलब्धियां भी गिनाईं

प्रधानमंत्री ने 75 हजार युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र, कहा

फिर भी हम संभल गए बहुतों का बुरा हाल

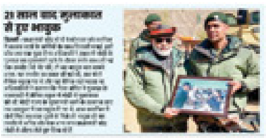

पीएम मोदी ने की ऋषि सुनक से बात

आर.एन.आई
DELHIN/2020/78812
16-30 नवंबर, 2022

न्यू इंडिया
समाचार
पाक्षिक

आरएनआई DELHIN/2020/78812, दिल्ली पोस्टल लाइसेंस नंबर- DL (S)-1/3550/2020-22 डब्ल्यूपीपी संख्या- U (S)-98/2020-22, posting at BPC, Meghdoot Bhawan, New Delhi - 110001 on 13-17 advance Fortnightly
(प्रकाशन तिथि-02 नवंबर 2022, कुल पृष्ठ-52)

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन

भारत की वैश्विक सोच का सारथी

पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के साथ 'एक सूर्य - एक विश्व - एक ग्रिड' का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र आज वैश्विक मंच पर गूंज रहा है तो इसके पीछे है पर्यावरण संरक्षण का वह विजन, जिस पर चल कर सिर्फ वादा नहीं बल्कि नई सोच के साथ काम करने की शुरुआत भारत ने की थी। 30 नवंबर 2015 का अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के रूप में पर्यावरण संरक्षण की ऐसी ही वैश्विक पहल की शुरुआत भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान की थी। 15 देशों के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर के साथ शुरू हुए इस गठबंधन में आज 109 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देश शामिल हैं। यह पहला ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसका मुख्यालय भारत में बनाया गया है। हाल ही में आयोजित इसकी महासभा में एक बार फिर भारत को इसकी अध्यक्षता और फ्रांस को सह अध्यक्षता सौंपी गई है...

“अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन दुनिया के लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण बनकर सामने आया। भारतीयों को इस बात की भी खुशी है कि आईएसए का मुख्यालय भारत में ही है। ये आईएसए के प्रति अपनत्व को और बढ़ाता है। मुझे लगता है जब भी भविष्य में 21वीं सदी में स्थापित मानव कल्याण के बड़े संगठनों की चर्चा होगी तो आईएसए का नाम उसमें सबसे ऊपर होगा। आईएसए के तौर पर हम सभी ने जलवायु न्याय को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा मंच तैयार किया है। आने वाली पीढ़ियों को मानवता से जुड़ा बहुत बड़ा उपहार हम सबने मिल कर दिया है।”

— नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रधान संपादक:
सत्येन्द्र प्रकाश, प्रधान महानिदेशक,
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

प्रकाशक और मुद्रक:
मनीष देसाई, महानिदेशक
केंद्रीय संचार ब्यूरो

कमरा संख्या-278, केंद्रीय संचार ब्यूरो,
सूचना भवन, द्वितीय तल,
नई दिल्ली- 110003 से प्रकाशित

मुद्रण: इनफिनिटी एडवर्टाइजिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड,
एफबीडी वन कॉर्पोरेट पार्क, 10वीं मंजिल, नई दिल्ली-
फरीदाबाद बॉर्डर, एनएच-1, फरीदाबाद-121003